जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 18 संख्याः 29 प्रभात चूरू, गुरूवार 28 मई, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

वेणुगोपाल ने कर्नाटक पर जानबूझकर प्रैस को भ्रमित किया था

बेंगलुरु में अलग ही नज़ारा दिखा। मु.मंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट को ब्रेकफास्ट दावत दी और राज्यपाल से भी मिलने का समय मांगा, शायद इस्तीफा देने के लिए

- जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो।

नई दिल्ली, 27 मई। पिछले हफ्ते जब डीके शिवकुमार से उनकी पदोन्नति की चर्चाओं के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था, "अच्छा समय आएगा।" अब, कर्नाटक में बड़े राजनीतिक बदलाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है और लगता है कि उनका समय सचमुच आ गया है। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस आलाकमान ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को शीर्ष पद सौंपने के लिए हरी झंडी दे दी है। अब सिर्फ एक सवाल बाकी है - कब?

- जानकार सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन सन्निकट है, उन्होंने इसके दो पहलू बताए।
- पहला तो यह कि सिद्धारमैया गुरुवार या शुक्रवार तक त्याग पत्र दे देंगे और फिर शुक्रवार या शनिवार को डीके शिवकुमार शपथ ले लेंगे।
- दूसरा यह कि अगर सिद्धारमैया कुछ वक्त लेते हैं तो शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा चुनाव के बाद होगा।
- सत्ता छोड़ने के एवज में सिद्धारमैया को राज्यसभा सीट, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में बड़ी भूमिका और शिवकुमार की सरकार में उनके समर्थकों को मंत्री पद दिए जाने की पेशकश की गई है, सिद्धारमैया ने इस पर सोचने का समय मांगा है। हालांकि माना जा रहा है कि सिद्धारमैया मान गए हैं।

सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को दिल्ली में चली लंबी बैठकों के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद छोड़कर डीके शिवकुमार को जिम्मेदारी सौंपने के लिए राजी कर लिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो किसी भी बदलाव से इनकार कर मीडिया को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन बेंगलुरु की गतिविधियां कुछ और ही संकेत दे रही हैं। सिद्धारमैया ने मंत्रिमंडल के लिए नाश्ते का आयोजन किया है और राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है, संभवतः इस्तीफा सौंपने के लिए।

मामले की जानकारी रखने वाले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी की गिरफ्तारी, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर, 27 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाला से जुड़े केस में बिना आधार बताए तत्कालीन मंत्री महेश जोशी को एसीबी की ओर से गिरफ्तार करने से जुड़े मामले में गृह विभाग और एसीबी के डीजी से

- जोशी के पुत्र ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा था कि लिखित रूप में कारण बताये बिना महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया।

जवाब मांगा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा गया कि एसीबी ने मामले में गत 7 मई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप की फिटनैस पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ी

मैमोरियल डे कार्यक्रम के दौरान ट्रंप लड़खड़ाते हुए दिखे, इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है

- जाल खंबाता -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 27 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप एक बार फिर ऑनलाइन बहस का केन्द्र बन गए हैं। "मेमोरियल डे" कार्यक्रम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे समारोह के दौरान खड़े लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से साझा किए गए इस वीडियो में ट्रंप को कार्यक्रम के दौरान फहराते हुए झंडों के बीच थोड़ा हिलते- डुलते और लड़खड़ाते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद ऑनलाइन आलोचकों ने राष्ट्रपति के स्वास्थ्य और फिटनेस को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने दावा किया कि सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान वे अस्थिर दिख रहे थे।

हालांकि ट्रंप समर्थकों ने इन आलोचनाओं को खारिज कर दिया और कहा कि वीडियो को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। कई लोगों का कहना था कि यह बहुत मामूली हरकत थी और संभवतः लंबे समय तक खुले मैदान में खड़े रहने की वजह से ऐसा हुआ।

- ट्रंप समर्थकों ने फिटनैस संबंधी सवालों को खारिज कर दिया और कहा कि लंबे समय तक खड़े होने के कारण ऐसा हुआ है।
- लेकिन ट्रंप का लड़खड़ाने वाला वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और शेयर किया जा चुका है और अमेरिका के चुनावी माहौल में इसे लेकर बहस छिड़ गई है।

मेमोरियल डे कार्यक्रम उन अमेरिकी सैनिकों को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया था, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण गंवाए। ट्रंप इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के साथ शामिल हुए, जहां शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई।

यह वीडियो अब तक ऑनलाइन लाखों बार देखा जा चुका है, जिससे अमेरिकी चुनाव के मौसम से पहले ट्रंप को लेकर चल रही राजनीतिक जांच और बहस और तेज हो गई है। हाल के वर्षों में अमेरिका में राजनीतिक नेताओं के स्वास्थ्य और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके व्यवहार को लेकर ऐसी बहसें अक्सर वायरल होती रही हैं।

ट्रंप या वाइट हाउस की ओर से इस वीडियो को लेकर उठ रही अटकलों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

राजस्थान हाईकोर्ट से सलमान खान को एक और राहत मिली

राजश्री पान मसाले के विज्ञापन को लेकर जिला उपभोक्ता मंच द्वारा सलमान खान की उपस्थिति और हस्ताक्षर मिलान के आदेश पर अदालत ने रोक लगाई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में जिला उपभोक्त मंच, कोटा के 6 जनवरी के उस फैसले पर भी रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि सलमान खान स्वयं उपभोक्ता न्यायालय में उपस्थित हों। साथ ही अपने कोई ऐसे दस्तावेज साथ लेकर आएं, जिसमें उनके हस्ताक्षर से मिलान किया जा सकें। क्योंकि इस प्रकरण में सलमान की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में किए गए हस्ताक्षरों पर भी संदेह जताया जा रहा है। जिला उपभोक्ता मंच ने सलमान खान के हस्ताक्षर की एफ.एस.एल. जांच करवाने के भी आदेश दिए थे। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने बुधवार को यह आदेश सलमान खान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई यह रोक इस प्रकरण की अगली सुनवाई तक ही रहेगी, जो कि 6 जून को तय की गई है। इस मामले में सलमान की ओर से अधिवक्ता शिवांशु नवल और वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा व उनके सहायक अधिवक्ता योगेश कल्ला पैरवी के लिए पेश हुए थे।

- हालांकि हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई यह रोक इस प्रकरण की अगली सुनवाई तक ही रहेगी, जो कि 6 जून को तय की गई है।

ज्ञात रहे कि जिला उपभोक्ता आयोग में 12 दिसंबर 2025 को योगेन्द्र सिंह द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि राजश्री पान मसाला और सलमान खान तंबाकु के प्रयोग को लेकर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता मंच ने 6 जनवरी 2026 को विज्ञापन पर रोक लगायी थी और यह आदेश कंपनी और सलमान खान का पक्ष सुने बिना ही दे दिए गए थे। साथ ही यह भी कहा गया था कि राजश्री पान मसाला कंपनी पर यह आदेश तब तक लागू रहेगा, जब तक कि वह अपना जवाब पेश नहीं कर देती। इसके बाद 15 जनवरी 2026 को जब कंपनी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर दिया गया था, इसके बावजूद भी जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने 6 जनवरी के आदेश को नहीं हटाया, उल्टा सलमान खान के हस्ताक्षरित शपथ पत्र में हस्ताक्षर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पंचायत निकाय चुनाव में संयम लोढा ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट लगाई

जयपुर, 27 मई। प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ की ओर से दिए गए फैसले के संबंध में पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर की गई है। इसमें कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को यदि राज्य सरकार या राज्य

- केविएट में कहा गया है कि यदि राज्य सरकार या राज्य चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में अपील करें तो प्रार्थी की सुने बिना आदेश नहीं दें।

चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं तो कोई भी आदेश देने से पहले प्रार्थी का पक्ष भी सुना जाए और उसके बाद ही कोई आदेश दिया जाए। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में आदेश जारी कर पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शांति समझौते के लिए ईरान ने कठोर शर्तें लगाईं

संभावना है कि अमेरिका इन शर्तों को शायद स्वीकार नहीं करेगा

- सुकुमार साह -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 27 मई। ईरान, वॉशिंगटन के साथ चल रही बेहद अहम बातचीत में दो ऐसी मांगें लेकर उतरा है, जिन पर वह किसी भी हालत में समझौता करने को तैयार नहीं है।

पहली मांग यह है कि ईरान को आर्थिक राहत दी जाए। इसके तहत प्रतिबंधों में ढील, वैश्विक तेल बाजारों तक फिर से पहुंच और विदेशों में जमा अपनी अरबों डॉलर की फ्रीज़ की गई संपत्ति की रिहाई चाहता है। माना जा रहा है कि ईरानी अधिकारी पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रोके गए लगभग 100 अरब डॉलर में से कम से कम कुछ हिस्से तक पहुंच चाहते हैं।

दूसरी मांग यह है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य दबाव कम किया जाए। इसमें होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास नौसैनिक प्रतिबंधों में ढील और भविष्य में अमेरिकी सैन्य हमलों के खिलाफ आश्वासन शामिल हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, बातचीत में ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, जिनमें होर्मुज़ स्ट्रेट से बिना रोक-टोक व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही बहाल करने के बदले, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम करने की बात शामिल है।

एक और बड़ा विवाद का मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम बना हुआ है। तेहरान अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को पूरी तरह सौंपने की मांग का विरोध कर रहा है और उसका कहना है कि उसकी परमाणु गतिविधियां शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हैं। ईरानी वार्ताकार चाहते हैं कि किसी भी समझौते में देश के भीतर कुछ स्तर तक यूरेनियम संवर्धन की क्षमता बनी रहे, क्योंकि वह इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला मानता है।

- ईरान की पहली शर्त है, ईरान को आर्थिक राहत दी जाए, प्रतिबंधों में ढील दी जाए और विदेशों में फ्रीज संपत्ति छोड़ी जाए।
- ईरान की दूसरी शर्त है, खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य दबाव कम किया जाए। इसमें होर्मुज़ स्ट्रेट के पास से नौसैनिक प्रतिबंधों में ढील भविष्य में अमेरिकी हमलों के खिलाफ आश्वासन भी शामिल है।
- इसके अलावा ईरान अपना यूरेनियम भंडार भी पूरी तरह सौंपना नहीं चाहता। ईरान कुछ स्तर तक यूरेनियम संवर्धन की क्षमता बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वह इसे राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला मानता है।

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इन शर्तों को स्वीकार करेंगे या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि वे किसी बड़े शांति समझौते के बजाय सीमित और व्यावहारिक समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं। ट्रंप चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील, ईरान के फ्रीज़ किए गए फंड की आंशिक रिहाई और सैन्य तनाव कम करने पर विचार कर सकते हैं, यदि ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही की गारंटी दे और अपने परमाणु ठिकानों की कड़ी निगरानी के लिए राजी हो जाए।

तथापि, दोनों पक्षों के सामने बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक मजबूरियाँ है। ट्रंप कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि यदि ईरान किसी समझौते का उल्लंघन करता है तो सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। वहीं, प्रभावशाली रिपब्लिकन नेता और इज़रायल समर्थक समूह किसी भी ऐसे समझौते का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा कोई भी समझौता अधिकतम दबाव की नीति को कमजोर करेगा। दूसरी ओर, अमेरिका, ईरान की परमाणु क्षमता पर कहीं ज्यादा सख्त पाबंदियां लगाने की मांग पर अड़ा हुआ है, जिसके लिए तेहरान अभी तैयार नहीं है।

ऐसे में फिलहाल सबसे संभावित नतीजा कोई व्यापक शांति समझौता नहीं, बल्कि सीमित लेन-देन आधारित समझ हो सकती है। इसके तहत, ईरान खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम कर सकता है और जहाजों की आवाजाही बहाल कर सकता है, जबकि अमेरिका प्रतिबंधों में सीमित राहत और कुछ आर्थिक रियायतें दे सकता है। दोनों पक्ष क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नेतृत्व अपने देश में राजनीतिक रूप से कमजोर दिखाई नहीं देना चाहता। यही कारण है कि समय-समय पर सैन्य टकराव और तीखी बयानबाजी जारी रहने के बावजूद बातचीत भी साथ-साथ चल रही है।

नीट पेपर लीक में दो और गिरफ्तार

नई दिल्ली, 27 मई। सीबीआई ने नीट-यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच के दौरान दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनको मिलाकर इस मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 13 हो गई है। गिरफ्तार किए गए लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरुरे

- लातूर के डॉ. मनोज शिरुरे और पुणे के तेजस हर्षद कुमार शाह की गिरफ्तारी से पकड़े गए लोगों की संख्या 13 हो गई है।

की तीन छात्रों की मदद करने में अहम भूमिका है। इनमें एक कोचिंग सेंटर के मालिक का बेटा भी है। उन्होंने आरोपी पी.वी. कुलकर्णी से केमिस्ट्री के प्रश्न हासिल करने में इन छात्रों की मदद की।

सीबीआई ने तेजस हर्षदकुमार शाह को भी गिरफ्तार किया है। वह पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर, डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी (एपीएमए) में फिजिक्स का फैकल्टी है। जांच में खुलासा हुआ है कि उसे लीक हुए फिजिक्स के प्रश्न मनीषा हवलदार से मिले थे। मनीषा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

सीबीआई ने विज्ञिप्त में यह जानकारी देते हुए कहा कि पूरी कड़ी और साज़िश का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अब तक अलग-अलग जगहों पर 49 स्थानों पर तलाशी ली गई है।

तीन दिन आँधी-बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली, 27 मई। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में 28 मई से आंधी, बारिश और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम में बदलाव के साथ तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है।

राजस्थान में 28, 29 और 30 मई को बारिश, गरज-चमक और तेज

- मौसम विभाग ने राजस्थान में 28 से 30 मई तक आँधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है, इससे गर्मी में राहत मिल सकती है।

आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि धूल भरी आंधी कई जगहों पर बवंडर का रूप भी ले सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

पाक की दुविधा, ट्रंप की मानी तो जनता नाराज़ होगी, न मानी तो जो पाया वो गंवाना पड़ेगा

असल में ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते में 6 मुस्लिम देशों द्वारा अब्राहम अकॉर्ड को स्वीकार करने की शर्त जोड़ दी है, यानि उन्हें इज़रायल से संबंध सामान्य करने होंगे।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 27 मई। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टुथ सोशल पोस्ट ने 6 मुस्लिम देशों में हलचल मचा दी है। इस पोस्ट में उन्होंने ईरान के साथ शांति समझौते को छह मुस्लिम देशों द्वारा "अनिवार्य" और "एक साथ" अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने से जोड़ा है। इन देशों में सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान शामिल हैं।

अब्राहम समझौते इज़रायल और अरब देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की शृंखला हैं। ये समझौते मिडिल ईस्ट में व्यापार, कूटनीति व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने करवाए थे। इनका नाम पैगम्बर इब्राहिम के नाम पर रखा गया, जिन्हें मुस्लिम, यहूदी, ईसाई सभी मानते हैं। सबसे पहले यूएई और बहरीन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। बाद में मोरक्को, सूडान, जॉर्डन भी इसमें शामिल हो गए थे।

पाकिस्तान मामलों के विशेषज्ञ पत्रकार सुशांत सरीन का कहना है कि कोई भी यह नहीं समझ पा रहा कि मनमौजी अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नई मांग पर कैसी प्रतिक्रिया दी जाए। यह भी साफ नहीं है कि ट्रंप ने यह बात सिर्फ यूं ही कही है या वे वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

फिर भी, ट्रंप ने शर्तें बदलकर क्षेत्रीय देशों के सामने गंभीर दुविधा खड़ी कर दी है। अगर वे अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं, तो वे न केवल ट्रंप के गुस्से को न्योता देंगे, बल्कि क्षेत्र की पहले से तनावपूर्ण सुरक्षा स्थिति के और बिगड़ने का खतरा भी रहेगा। दूसरी ओर, अगर वे ट्रंप के दबाव के आगे झुकते हैं, तो उन्हें अपने देशों में आंतरिक अशांति और जनता के विरोध का सामना करना पड़ सकता है।

- ट्रंप ने अपनी पोस्ट में आठ देशों का उल्लेख किया है। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, लेकिन पहले तीन देशों का ही विशेष महत्व है। बहरीन व यूएई इस समझौते पर साइन कर चुके हैं तथा टर्की, मिस्र, जॉर्डन के इज़रायल से कूटनीतिक संबंध हैं।
- हालांकि, ट्रंप ने पाकिस्तान को हस्ताक्षर से छूट की राहत दी, पर, उनकी पोस्ट में यह भी कहा कि अगर कोई देश अब्राहम अकॉर्ड पर साईन नहीं करता है तो उसे ईरान डील का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
- बस इसी बात ने पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी है, पाकिस्तान ने हालांकि पुराना रुख दोहराया, कि, कायदे आज़म जिन्ना ने इज़रायल को मान्यता नहीं देने का प्रावधान किया था पर, उसे डर है कि हाल ही में अमेरिका की मेहरबानी से मिडिल ईस्ट में उसने जो साख बनाई है, वह कहीं छिन ना जाए।

अपनी पोस्ट में ट्रंप ने आठ देशों का उल्लेख किया- सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, टर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और यूएई। लेकिन अब्राहम समझौते के नजरिए से इनमें केवल पहले तीन देशों का ही विशेष महत्व है।

बहरीन और यूएई पहले ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। तुर्की, मिस्र और जॉर्डन के इज़रायल के साथ राजनयिक संबंध हैं। ट्रंप ने कहा, एक या दो देशों को तुरंत हस्ताक्षर न करने के लिए छूट दी जा सकती है, और उन्होंने "उदारता" दिखाते हुए कहा कि इसे स्वीकार किया जाएगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के साथ अन्याय कब तक?

एक समय था जब विश्वविद्यालय में शिक्षक बनना केवल नौकरी नहीं, बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा और बौद्धिक गौरव का प्रतीक माना जाता था। राजस्थान सहित पूरे देश में विश्वविद्यालयों की पहचान ज्ञान, शोध और उत्कृष्ट शिक्षण के केंद्रों के रूप में होती थी। विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक समाज के सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित वर्ग में गिने जाते थे। उस दौर में विश्वविद्यालयों के वेतनमान राजकीय महाविद्यालयों की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक थे और योग्य शिक्षाविद विश्वविद्यालयों में आने को अपना सौभाग्य मानते थे।

लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जिन विश्वविद्यालयों को कभी राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला कहा जाता था, वे अब सरकारी उपेक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण और वित्तीय भेदभाव के शिकार बन चुके हैं। सबसे अधिक पीड़ा की बात यह है कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

सत्तर और अस्सी के दशक में विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट विद्वानों को आकर्षित करने के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूर्व सेवाओं का समायोजन और सम्मानजनक सेवा शर्तें दी जाती थीं। कई बार तो केवल योग्यता और शोध उपलब्धियों के आधार पर प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को विश्वविद्यालयों में नियुक्त कर लिया जाता था। दूसरी ओर राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतनमान सामान्य सरकारी अधिकारियों के समान था और उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी केवल 55 वर्ष थी। जबकि विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी। यही कारण था कि महाविद्यालयों के शिक्षक विश्वविद्यालयों में आने के लिए उत्सुक रहते थे।

समय बदला और राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर भी लगातार प्रहार शुरू हो गए। सरकार ने विश्वविद्यालयों को एमओयू के माध्यम से अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया और स्पष्ट संकेत दिया कि निर्देशों की अवहेलना करने पर अनुदान रोका जा सकता है। परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय अब स्वतंत्र शैक्षिणक संस्थान न रहकर सरकारी विभागों की तरह संचालित होने लगे हैं।

आज विश्वविद्यालयों की हालत चिंताजनक है। शिक्षकों के लगभग 80 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। प्रतिभाशाली युवा अब विश्वविद्यालयों में करियर बनाने से बच रहे हैं। शोध और अकादमिक गुणवत्ता लगातार गिर रही है। छोटी-छोटी प्रशासनिक स्वीकृतियों के लिए भी राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक हो गई है। यह स्थिति केवल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर हमला नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की सुनियोजित प्रक्रिया प्रतीत होती है।

अब समय आ गया है कि सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों के साथ हो रहे इस भेदभाव को समाप्त करे, लंबित वित्तीय लाभ तुरंत प्रदान करे, रिक्त पदों को भरे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करे। अन्यथा इतिहास यह दर्ज करेगा कि जिस राज्य ने कभी शिक्षा और विद्वता की परंपरा पर गर्व किया था, उसी ने अपने विश्वविद्यालयों को धीरे-धीरे कमजोर होने दिया।

सबसे बड़ा अन्याय वेतन विसंगतियों के मामले में सामने आया है। राजस्थान सरकार ने छठे वेतनमान के बाद उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने के लिए 6 अप्रैल 2013 को अधिसूचना जारी की, जिसके तहत 2 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 के बीच वार्षिक वेतन वृद्धि पाने वाले कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने का प्रावधान किया गया। यह लाभ राज्य कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालयों के अशैक्षिणक कर्मचारियों को भी दिया गया।

इसके बाद राजकीय महाविद्यालय शिक्षकों ने भी यह लाभ मांगा और सरकार ने 10 मई 2021 को अधिसूचना जारी कर उन्हें यह सुविधा प्रदान कर दी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से विश्वविद्यालय शिक्षकों को इस लाभ से वंचित रखा गया।

कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने जब यह मुद्दा उठाया, तब संबंधित विश्वविद्यालयों ने सरकार से अनुमति मांगी। चार वर्षों तक फाइलें घूमती रहीं, आंकड़े जुटाए जाते रहे और अंततः यह तर्क दिया गया कि यदि कृषि विश्वविद्यालय शिक्षकों को यह लाभ दे दिया गया तो अन्य विश्व विद्यालय के शिक्षक भी ऐसी मांग करेंगे और सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।

यह तर्क न केवल हास्यास्पद है बल्कि गहरे भेदभाव को भी उजागर करता है। लाखों सरकारी कर्मचारियों और हजारों महाविद्यालय शिक्षकों को यह लाभ देते समय सरकार को वित्तीय भार महसूस नहीं हुआ, लेकिन विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के मामले में अचानक खजाना खाली दिखाई देने लगा। क्या विश्वविद्यालयों के शिक्षक इस राज्य के कर्मचारी नहीं हैं? क्या उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए?

सच्चाई यह है कि सरकार की इस उपेक्षापूर्ण नीति ने विश्वविद्यालयों का मनोबल तोड़ दिया है। योग्य शिक्षक हतोत्साहित हैं, नई प्रतिभाएँ विश्वविद्यालयों में आने से बच रही हैं और शोध तथा अकादमिक गुणवत्ता लगातार गिर रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में विश्वविद्यालय केवल डिग्री बाँटने वाले संस्थान बनकर रह जाएंगे।

राज्य सरकार को समझना होगा कि विश्वविद्यालय केवल भवनों और प्रशासनिक ढाँचों का नाम नहीं हैं। विश्वविद्यालयों की आत्मा उनके शिक्षक होते हैं। यदि शिक्षकों को सम्मान, समानता और न्याय नहीं मिलेगा तो उच्च शिक्षा व्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती।

अब समय आ गया है कि सरकार विश्वविद्यालय शिक्षकों के साथ हो रहे इस भेदभाव को समाप्त करे, लंबित वित्तीय लाभ तुरंत प्रदान करे, रिक्त पदों को भरे और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बहाल करे। अन्यथा इतिहास यह दर्ज करेगा कि जिस राज्य ने कभी शिक्षा और विद्वता की परंपरा पर गर्व किया था, उसी ने अपने विश्वविद्यालयों को धीरे-धीरे कमजोर होने दिया।

–अतिथि सम्पादक,
डा. पी. सी. कंठालिया
पूर्व प्रोफेसर एवं मुख्या मृदा वैज्ञानिक
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, उदयपुर

राशिफल गुरूवार 28 मई, 2026

पंडित अनिल शर्मा

प्रथम ज्येष्ठ मास (अधिक), शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2083, चित्रा नक्षत्र प्रातः 8:08 तक, वारियान योग रात्रि 3:55 तक, बालव करण प्रातः 7:57 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-वृष, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मेष, बुध-वृष, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज प्रदोष व्रत, ईद-उल-जुहा (बकरीद) मु. है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ सूर्योदय से 7:19 तक, चर 10:42 से 12:24 तक, लाभ अमृत 12:24 से 3:47 तक, शुभ 5:28 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:38, सूर्यास्त 7:10

मेष

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

धनु

आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कुंभ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कर्क

व्यावसायिक एवं नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

वृश्चिक

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

गांव की चौपाल से शासन की चौखट तक : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संवाद आधारित प्रशासन

राजेन्द्र गहलोत

राजनीति और प्रशासनिक परंपरा में जनसंवाद को हमेशा एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों गाँव-गाँव जाकर ग्राम चौपाल, रात्रि विश्राम, सुबह का भ्रमण और आमजन से प्रत्यक्ष संवाद कर शासन की शैली को नई दिशा दे रहे हैं। यह दौरे सत्ता और समाज के बीच उस दूरी को कम करने का सार्थक प्रयास हैं, जो अक्सर प्रशासनिक ढांचे में दिखाई देती है।

राजस्थान जैसे विशाल और विविधताओं वाले राज्य में शासन केवल सचिवालयों और बैठकों से संचालित नहीं हो सकता। यहाँ रेगिस्तान की पीड़ा अलग है, आदिवासी अंचलों की आवश्यकताएँ अलग हैं और सीमावर्ती गाँवों की चुनौतियाँ अलग। ऐसे में मुख्यमंत्री का सीधे गाँवों में पहुँचकर लोगों की बात सुनना लोकतांत्रिक संवेदनशीलता का परिचायक है।

मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारतीय राजनीति में गाँवों के दौरे सामान्य बात हैं, लेकिन किसी मुख्यमंत्री का गाँव में रुककर वहाँ की वास्तविक परिस्थितियों को समझने का प्रयास प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब कोई जनप्रतिनिधि गाँव में रात बिताता है तो उसे केवल मंच से दिखाई देने वाला विकास नहीं, बल्कि पानी की समस्या, बिजली की स्थिति, स्कूलों की वास्तविकता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यही अनुभव नीतियों को व्यवहारिक बनाता है।

प्रातःकालीन ग्राम भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री का महिलाओं, बुजुर्गों, किसानों और बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना भी इस अभियान की बड़ी विशेषता बनकर उभरा है। सामान्यतः सरकारी कार्यक्रमों में केवल चुनिंदा प्रतिनिधियों या अधिकारियों से संवाद होता है। मुख्यमंत्री सीधे ग्रामीण महिलाओं से पेयजल, गैस, राशन या शिक्षा की जानकारी लेते है और इससे प्रशासनिक फाइलों के पीछे छिपी वास्तविकता सामने आती है। इसी प्रकार बच्चों से शिक्षा और युवाओं से रोजगार पर चर्चा शासन की प्राथमिकताओं को मानवीय स्वरूप देती है।

ग्रामीण राजस्थान में आज भी बड़ी संख्या में लोग जिला मुख्यालय या जयपुर तक अपनी बात नहीं पहुँचा पाते। ऐसे लोगों के लिए मुख्यमंत्री का स्वयं गाँव तक पहुँचना एक प्रकार से सरकार आपके द्वार की अवधारणा को व्यवहार में उतारने जैसा है। यह लोकतंत्र की उस भावना को मजबूत करता है जिसमें जनता केवल मतदाता नहीं, बल्कि शासन की सहभागी मानी जाती है।

इन दौरों का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ होने वाली समीक्षा बैठकें हैं। अक्सर विकास योजनाएँ कागजों में सफल दिखाई देती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी गति अपेक्षित नहीं होती। मुख्यमंत्री जब सीधे जिलों में जाकर अधिकारियों से जवाबदेही तय करते हैं, तो प्रशासनिक तंत्र में सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक है। इससे योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व संबंधी समस्याओं की वास्तविक स्थिति सामने आती है।

विशेष रूप से यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि इन बैठकों में केवल समीक्षा नहीं, बल्कि समस्याओं के त्वरित समाधान पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था में कई बार छोटी समस्याएँ केवल समन्वय के अभाव में वर्षों तक लंबित रहती हैं। मुख्यमंत्री स्तर पर सीधे हस्तक्षेप से ऐसे मामलों में गति आती है और अधिकारियों में भी जवाबदेही की भावना मजबूत होती है।

राजस्थान जैसे राज्य में जल संकट, ग्रामीण पलायन, बेरोजगारी और कृषि आधारित चुनौतियाँ निरंतर बनी रहती हैं और इन परिस्थितियों में शासन का संवेदनशील और सक्रिय होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री के ये दौरे ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं को पुनः केंद्र में लाने का संकेत भी हैं। लंबे समय तक विकास का विमर्श शहरी परियोजनाओं और बड़े निवेशों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा, जबकि राज्य की बड़ी आबादी अब भी गाँवों में निवास करती है। ऐसे में गाँवों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास प्रशासनिक संतुलन की दिशा में सकारात्मक कदम है।

राजनीतिक दृष्टि से भी यह अभियान महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का जनता के बीच जाना केवल चुनावी समय तक सीमित नहीं होना चाहिए। जनता यह महसूस करना चाहती है कि सरकार उनकी समस्याओं को सुन रही है और उनके जीवन से जुड़ी चुनौतियों को समझ रही है। मुख्यमंत्री के इन दौरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में यह संदेश देने का प्रयास किया है कि सरकार केवल जयपुर तक सीमित नहीं है।

इन दौरों से प्राप्त अनुभवों को नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में जल संकट प्रमुख समस्या है तो वहाँ दीर्घकालिक जल संरक्षण योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ग्रामीण युवाओं में रोजगार की चिंता अधिक दिखाई देती है तो कौशल विकास और स्थानीय रोजगार आधारित योजनाओं को गति मिल सकती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लिए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली का यह पक्ष इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि आज की राजनीति में जनसंपर्क अक्सर सोशल मीडिया और बड़े आयोजनों तक सीमित होता जा रहा है। ऐसे समय में गाँवों की गलियों में जाकर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना पारंपरिक जननेतृत्व की याद दिलाता है। भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति भी इसी प्रत्यक्ष संवाद में निहित है।

मुख्यमंत्री का यह अभियान आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास प्रतीत होता है। यदि यह अभियान निरंतरता और परिणाम दोनों के साथ आगे बढ़ता है, तो यह राज्य में उत्तरदायी और संवाद आधारित शासन का एक प्रभावी मॉडल बन सकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि ग्राम चौपाल, रात्रि विश्राम और जनसंवाद केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन की संवेदनशीलता की परीक्षा हैं। मुख्यमंत्री का यह प्रयास ग्रामीण राजस्थान की आवाज़ को सीधे सत्ता के केंद्र तक पहुँचाने का माध्यम बन सकता है। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति भी यही है कि सरकार जनता तक पहुँचे, जनता की सुने और समस्याओं के समाधान के लिए जवाबदेह बने। राजस्थान में चल रहा यह संवाद अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।

–राजेन्द्र गहलोत,
राज्यसभा सांसद

उच्च शिक्षा के प्रति सामाजिक उदासीनता - अभिभावकों की खामोशी

अशोक कुमार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा जगत में एक नई सुबह की उम्मीद लेकर आई है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर सामाजिक संगठनों के माध्यम से पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा का क्षेत्र आज एक गहरे संकट से जूझ रहा है। वर्तमान में उच्च शिक्षा की स्थिति स्कूलों की तुलना में कहीं अधिक चिंताजनक है। इसका मुख्य कारण शिक्षा का वह व्यवसायीकरण है जिसने औपचारिक शिक्षण संस्थानों को केवल डिग्री बांटने वाले केंद्रों में बदल दिया है और कोचिंग सेंटरों को असली शिक्षा का मंदिर बना दिया है।

डमी स्कूल और कोचिंग संस्कृतिः एक समानांतर व्यवस्था

आज की सबसे बड़ी विडंबना डमी स्कूल और नॉन-अटेंडिंग कॉलेज हैं।

संस्थानों का खोखलापनः छात्र केवल कागजों पर स्कूल या कॉलेज में नामांकित होते हैं, जबकि उनका पूरा समय कोचिंग सेंटरों में बीतता है। इससे औपचारिक शिक्षण संस्थानों का शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह नष्ट हो चुका है।

व्यक्तित्व विकास की बलिः स्कूल और कॉलेज केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार, नैतिकता, खेल और अनुशासन सीखने के केंद्र होते हैं। डमी कल्चर के कारण छात्र इन जीवन-कौशलों से वंचित रह जाते हैं और केवल रैंक लाने वाली मशीन बनकर रह जाते हैं।

अभिभावकों की भूमिका और संवादहीनता-उच्च शिक्षा के इस बिगाड़ में अभिभावकों का रवैया भी एक महत्वपूर्ण कारक है।

अभिभावकों की चुप्पीः अक्सर देखा जाता है कि स्कूल तक तो माता-पिता बच्चों की पढ़ाई में रुचि लेते हैं, लेकिन कॉलेज स्तर पर पहुँचते ही या तो वे बच्चों की बात नहीं सुनते या अभिभावक बच्चों को कुछ कहना छोड़ देते हैं।

कोचिंग को प्राथमिकताः अभिभावक स्वयं बच्चों को नियमित कॉलेज भेजने के बजाय कोचिंग सेंटरों की भारी-भरकम फीस भरना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि औपचारिक शिक्षा की डिग्री तो जुगाड़ से भी मिल जाएगी, असली मेहनत तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए करनी है।

विशेष खंडः कोचिंग हब का दबाव और मानसिक स्वास्थ्य का संकट - कोटा और जयपुर जैसे कोचिंग हब आज सफलता की फैक्ट्रियां तो बन गए हैं, लेकिन यहाँ से निकलने वाली खबरें दिल दहला देने वाली हैं।

एकाकीपन और अवसादः डमी स्कूलों के कारण छात्र अपने हमउम्र साथियों के साथ स्वस्थ सामाजिक वातावरण से कट जाते हैं। कोचिंग की 14-14 घंटे की पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा उन्हें एक ऐसे अंधेरे कमरे में धकेल देती है जहाँ केवल नंबर मायने रखते हैं।

अभिभावकों की अवास्तविक उम्मीदेंः अभिभावक बच्चों को कोचिंग में भेजकर यह मान लेते हैं कि अब उनका चयन निश्चित है। यह उम्मीद बच्चों पर 'प्रदर्शन के दबाव' के रूप में लद जाती है। जब बच्चा इस दबाव को नहीं झेल पाता, तो वह आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हो जाता है।

संवाद का अभावः घर से दूर हॉस्टलों में रह रहे छात्रों के पास कोई ऐसा मंच नहीं होता जहाँ वे अपना दुख साझा कर सकें। औपचारिक स्कूलों में होने वाली खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ तनाव कम करने का काम करती थीं, जो कोचिंग संस्कृति में पूरी तरह लुप्त हैं।

औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता और अप्रासंगिकता-यह एक कड़वा सच है कि आज सरकारी और कई निजी विश्वविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा की गुणवत्ता अत्यंत निम्न स्तर पर है।

अपडेटेड पाठ्यक्रम का अभावः पाठ्यक्रमों का उद्योगों की मांग या प्रतियोगी परीक्षाओं के स्तर से कोई मेल नहीं है।

मूल्यांकन पद्धतिः कॉलेज की परीक्षाएं केवल रटने की शक्ति की जांच करती हैं, जबकि प्रतियोगी परीक्षाएं तार्किक क्षमता की। यही कारण है कि छात्र औपचारिक कक्षाओं को समय की बर्बादी मानने लगते हैं।

क्रांतिकारी समाधानः अंकों का एकीकरण और पात्रता परीक्षा-इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान एकीकृत मूल्यांकन हो सकता है:-

यदि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतिम चयन में स्कूल और कॉलेज के क्वालीफाइंग एग्जाम्स (12वीं या स्नातक) के अंकों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए, तो छात्र और अभिभावक औपचारिक शिक्षा को गंभीरता से लेंगे। जब बोर्ड परीक्षाओं या स्नातक के अंकों की वैल्यू बढ़ेगी, तो छात्र डमी स्कूल के बजाय वास्तविक क्लासरूम में लौटेंगे। इससे कोचिंग का एकाधिकार खत्म होगा और छात्रों पर से एक ही परीक्षा में सब कुछ दांव पर लगाने का दबाव कम होगा। सामाजिक संस्थाओं और सरकार की जिम्मेदारी-उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इसे एक सामाजिक आंदोलन बनाना होगा:-

एनजीओ को अभिभावकों के साथ काउंसलिंग सत्र आयोजित करने चाहिए ताकि वे डमी स्कूल के खतरे और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को समझ सकें। सरकार को उन शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द करनी चाहिए जो केवल कागजों पर चल रहे हैं। साथ ही, कोचिंग संस्थानों के लिए कड़े रेगुलेशन एक्ट लागू करने चाहिए।

निष्कर्ष-उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सरकार को नीतियों में बदलाव कर औपचारिक शिक्षा के अंकों को प्रतियोगी परीक्षाओं में जोड़ना होगा। अभिभावकों को बच्चों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें डमी कल्चर के बजाय सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करना होगा। अंततः, जब औपचारिक शिक्षा का सम्मान बहाल होगा, तभी देश को वास्तव में योग्य, मानसिक रूप से स्वस्थ और चरित्रवान नागरिक मिलेंगे।

–प्रो. अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय गौरव की पुनःस्थापना का मोदी सरकार का अभियान रंग ला रहा है- नीदरलैंड से लाए गए लीडेन प्लेट्स

बाचाराम बघेल

राष्ट्र का अर्थ है, साझा इतिहास, साझा संस्कृति और साझा विश्वास-साझा उम्मीदों-सपनों में आम नागरिक की भागीदारी। कई विद्वानों ने बार-बार कहा कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिन्दू है, चाहे उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो क्योंकि हमारा इतिहास, संस्कृति और पूर्वज साझा हैं। राष्ट्रवाद की इसी बुनियाद को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार मजबूत किया है। चाहे अयोध्या में राम मंदिर का मसला हो या पूर्व में देश के मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों से लूट कर विदेश ले जाई गई कलाकृतियों, पाण्डुलिपियों व मूर्तियों को वापस लाने का मुद्दा हो, हर मोर्चे पर मोदी सरकार ने राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा किया है।

पीएम नरेन्द्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान गत 16 मई को नीदरलैंड के पीएम रॉब जैटेन की उपस्थिति में 11वीं सदी की चोलकालीन कॉपर प्लैट्स भारत को सौंपी गई। यूरोप में लीडेन प्लेट्स और भारत में अनाइमंगलम ताम्रपत्र के नाम से मशहूर ये प्राचीन अभिलेख, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति के महत्वपूर्ण जीवित साक्ष्य हैं। अब तक ये लीडेन शहर स्थित एशियाई लाइब्रेरी ऑफ लीडेन यूनिवर्सिटी में रखे हुए थे।

ये 30 किलोग्राम वजनी 21 बड़ी और 3 छोटी प्लैट्स का कलेक्शन है जिसमें चोल शासक राजराजा प्रथम द्वारा नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार के रोजमर्रा खर्च के लिए समीप के गांव अनाईमंगलम ग्राम व इसके आसपास के क्षेत्र के भू-राजस्व की आय विहार को देने के शाही फरमान के साथ ही राजराज प्रथम के उत्तराधिकारी राजेन्द्र चोल प्रथम द्वारा इस फरमान की पुष्टि का शाही फरमान शामिल हैं।

यह विहार श्रीविजय साम्राज्य के शासक मारविजयतुंग वर्मन ने 1006 ई. में निर्मित करवाया था। श्रीविजय साम्राज्य आज के इंडोनेशिया के सुमात्रा में केन्द्रित था। चोल शासक शैव थे और बौद्ध विहार निर्माण की अनुमति और उसके खर्च के लिए धन की व्यवस्था उस काल में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता की भारतीय भावना को उजागर करती है।

इन 21 तांबे की प्लेटों को शाही चोल मुहर वाली एक विशाल कांस्य (ब्रॉन्ज़) की अंगूठी से बांधा गया है, जिस पर चोल साम्राज्य का प्रतीक बाघ अंकित है। इनमें तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं का उपयोग किया गया है। 1690 ई. के दशक में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय नागापट्टनम में रहने वाले फ्लोरेंटियस कैंपर नाम का डच अधिकारी इन्हें भारत से बाहर ले गया, जिसके बाद से ये नीदरलैंड में रखे हुए थे।

26 मई, 2014 को नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही देश में राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव की नई भावना का दौर शुरू हुआ। विदेशी हमलावरों द्वारा संस्थागत और गैर संस्थागत रूप से लूटी, कब्जाई गई और चोरी गई प्राचीन कलाकृतियों को वापस लाकर उन्हें मंदिरों, विहारों, पुस्तकालयों में पुनः स्थापित करने का महत्वपूर्ण अभियान शुरू हुआ। ये केवल अतीत की वस्तुएं ही नहीं हैं बल्कि भारत की विरासत और सभ्यता की एक अनमोल कहानी बयां करती हैं। इनकी घर वापसी सभी देशवासियों के लिए भावनात्मक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। पुरातन वस्तुएं मात्र कलात्मक वस्तुएं नहीं हैं बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, ऐतिहासिक निरंतरता और सभ्यतागत स्मृति की प्रतीक हैं।

इससे पूर्व नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट, वाशिंगटन से तीन ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियों की वापसी बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इनमें लगभग 990 ईस्वी की चोल काल की शिव नटराज प्रतिमा, 12वीं शताब्दी की सोमस्कंद (शिव और उमा) प्रतिमा और 16वीं शताब्दी की विजयनगर काल की संत सुंदरार और परवई की प्रतिमा शामिल हैं। ये प्रतिमाएं 20वीं शताब्दी के मध्य में अवैध रूप से भारत से विदेशों में ले जाई गई। शिव नटराज मूर्ति मूल रूप से यह तंजावुर जिले के श्री भाव औषदेश्वर मंदिर, संत सुंदरार और परवई प्रतिमा तमिलनाडु के वीरसोलपुरम गांव में स्थित शिव मंदिर व सोमस्कंद प्रतिमा तमिलनाडु के अलात्तूर गांव में विश्वनाथ मंदिर से सम्बंधित हैं।

2014 से लेकर अब तक, संस्कृति मंत्रालय, एएसआई, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों और प्रवर्तन एजेंसियों के नेतृत्व में निरंतर राजनयिक, कानूनी और संस्थागत प्रयासों के माध्यम से भारत ने गत 12 मई तक विभिन्न देशों से 666 प्राचीन वस्तुओं को सफलतापूर्वक वापस मंगवाया है, जिनमें से 653 वस्तुएं 2014 के बाद वापस लाई गई हैं। हाल ही में, भारतीय मूल की 657 कलाकृतियां अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय दूतावास को सौंपी गई हैं और एएसआई के विशेषज्ञों द्वारा उनके परिवहन और सत्यापन के लिए व्यवस्थाएं चल रही हैं।

जुलाई, 2014 में 11वीं शताब्दी की चोलकालीन श्री पुरांतन नटराज की कांस्य प्रतिमा, नवंबर, 2014 में अमेरिका से 61 विभिन्न प्राचीन कलाकृतियां, सितंबर, 2015 अमेरिका से 19 प्राचीन कलाकृतियां जिनमें चोलकालीन कांस्य तथा प्रस्तर प्रतिमाएं और उनके अवशेष, जनवरी, 2016 में अमेरिका से देवी नामक चोलकालीन कास्यं प्रतिमा लायी गई। नवंबर, 2016 में अमेरिका से 111, अप्रेल 2017 में सिंगापुर से 10 कलाकृतियां जिसमें मूर्तियां और पाण्डुलिपियां भी शामिल हैं, वापस आई। जुलाई 2019 में अमेरिका से 67 पुरातन कलाकृतियां जिनमें कास्यं प्रतिमा, मिट्टी के बर्तन शामिल हैं, जनवरी, 2020 में आस्ट्रेलिया से 17, अक्टूबर, 2020 में अमेरिका से 157, दिसंबर, 2021 में अमेरिका से 23, जुलाई 2022 में अमरिका से 70, मार्च, 2023 में नीदरलैण्ड से 16, जुलाई, 2023 में अमेरिका से 50, जनवरी, 2024 में अमेरिका से 29 कलाकृतियां लाई जा चुकी हैं।

इसके साथ ही भारत सरकार ब्रिटेन के साथ राजनयिक माध्यमों से कोहिनूर की वापसी का प्रयास कर रही है लेकिन ब्रिटिश सरकार और अदालतों का यह स्पष्ट मानना है कि 1849 में लाहौर की संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था, इसलिए यह एक वैध उपहार या अधिग्रहण था जबकि अन्य अधिकतर मामलों में पुरातात्विक महत्व की कलाकृतियों को लूटा या चोरी किया गया था। ब्रिटेन का रॉयल कलेक्शन कानून इन बेशकीमती वस्तुओं को स्थायी रूप से देश से बाहर भेजने या वापस करने की अनुमति नहीं देते फिर भी कोहिनूर को भारत लौटाने के लिए सरकारी स्तर पर सभी प्रयास जारी हैं।

–बाचाराम बघेल,
भाजपा कार्यकर्ता धौलपुर

सार-समाचार

ऑनलाइन सट्टे लगाते एक गिरफ्तार

झुंझुनूं (निसं)। बगड़ जिला पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर (आईपीएस) के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस थाना बगड़ एवं डीएसटी झुंझुनूं की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ बडी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक टेबलेट, दो मोबाइल फोन एवं ऑनलाइन सट्टेबाजी में प्रयुक्त अन्य जुआ सामग्री जब्त की है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय देवेन्द्र सिंह राजावत (आरपीएस) के मार्गदर्शन एवं वृत्ताधिकारी झुंझुनूं ग्रामीण हरिसिंह धायल (आरपीएस) के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी बगड दौलतराम (आरपीएस प्रोबेशनर) के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 27 मई को ग्राम नूनिया गोठडा में दबिश देकर यह सफलता प्राप्त की। पुलिस के अनुसार, मौके से आरोपी केहरसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी नूनिया गोठडा, पुलिस थाना बगड, जिला झुंझुनूं को ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक टेबलेट, दो मोबाइल फोन तथा सट्टे से संबंधित अन्य सामग्री बरामद हुई। आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस कार्रवाई में बगड़ थाना पुलिस एवं डीएसटी झुंझुनूं की संयुक्त टीम ने तकनीकी इनपुट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा।

मोतियाबिंद जांच शिविर आयोजित

रतनगढ़ (निसं)। मानव सेवा और नेत्र ज्योति बचाने के उद्देश्य से रतनगढ़ माहेश्वरी सभा ट्रस्ट, शंकरा आई हॉस्पिटल, जिला अंधता निवारण समिति जयपुर एवं इन्द्रचन्द वेलफेयर ट्रस्ट कोलकाता के संयुक्त तत्वावधान में माहेश्वरी भवन परिसर में 39वें निःशुल्क मोतियाबिंद जांच एवं नेत्र लैंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे, जहां 135 मरीजों की मोतियाबिंद जांच की गई तथा 46 मरीजों का आधुनिक तकनीक से निःशुल्क ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। ट्रस्टी एवं शिविर प्रभारी नरेंद्र झंवर ने बताया कि चयनित मरीजों को ऑपरेशन हेतु जयपुर भेजा गया, जहां गुरुवार को बिना टांके की आधुनिक तकनीक से नेत्र लैंस प्रत्यारोपण किया जाएगा। वहीं अन्य मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई।शिविर का शुभारंभ भगवान शंकर की प्रतिमा के समक्ष राकेश जाजू, अर्चित झंवर, मांगीलाल स्वामी, महेश जाजू, डॉ. आशना गुप्ता, एडवोकेट कमल सोनी एवं नन्दकिशोर माटोलिया ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर एडवोकेट रजनीकांत सोनी ने अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। शिविर में शोभित जाजू, मुरलीधर मंडगिरा, एडवोकेट रामोतार ठठेरा, महावीर रामगढ़िया, महेंद्र पारीक राजलदेसर, बद्रीप्रसाद पारीक, मोहम्मद जमील बेहरीन, वासुदेव चाकलान सहित अनेक गणमान्यजन मौजूद रहे।

निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिये वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन आमंत्रित

हनुमानगढ़, (निसं)। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से रेल यात्रा द्वारा भारत के 15 तीर्थ स्थलों (ए.सी ट्रेन के माध्यम से) एवं हवाई यात्रा के माध्यम से पशुपतिनाथ (काठमांडू) नेपाल की निःशुल्क यात्रा हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि आवेदन पोर्टल2...विभाग की वेबसाईट...पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके भरे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन करने की सुविधा समस्त ई-मित्र पर भी उपलब्ध है। आवेदन करने के लिये पात्रता राजस्थान राजय का मूल निवासी हो, आयकरदाता नहीं हो, पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया हो, यात्रा करने हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से समक्ष हो एवं 60 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर ली हो। शेष अन्य शर्ते विभाग की वेबसाईट हिन्दी में देवस्थान डिपार्टमेंट राजस्थान पर देखी जा सकती है। यात्रा हेतु आवेदन प्रक्रिया 27 मई 2026 से प्रारंभ होकर अन्तिम 10 जून 2026 तक रहेगी। आवेदन में संशोधन अन्तिम दिनांक तक ही किये जा सकेंगे। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ कार्यालय में एवं कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01552-294677 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर की नई कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित

सादुलपुर, (निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर ब्लॉक राजगढ़ एवं ब्लॉक सिधमुख की तहसील कार्यकारिणी के चुनाव बुधवार को दलित छात्रावास राजगढ मे संपन्न हुए। दोनों ब्लॉकों में सभी पदाधिकारियों का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ। चुनाव प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई, जिस पर शिक्षकों ने हर्ष व्यक्त किया। शाम पांच बजे दी जानकारी के अनुसार राजगढ ब्लॉक में अध्यक्ष पद पर सुरेंद्र सिंह बौद्ध, कोषाध्यक्ष पद पर पवन गोठवाल, सभा अध्यक्ष पद पर राजवीर सुडा तथा महामंत्री पद पर चंद्रभान मेहरा निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं सिधमुख ब्लॉक में अध्यक्ष पद पर किरण भाटी, सभा अध्यक्ष पद पर रोहतास सिंह खींची, कोषाध्यक्ष पद पर गजेंद्र सिंह बौद्ध, महामंत्री पद पर अनिल पटीर तथा उपाध्यक्ष पद पर सेवानंद चौहान निर्विरोध चुने गए। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शिक्षकों एवं संगठन के सदस्यों ने स्वागत करते हुए उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षक हितों की रक्षा एवं संगठन को मजबूत बनाने के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे।

टीनशेड का उद्घाटन किया

उदयपुरवाटी (निसं)। पावर हाउस में विधुत विभाग के सेवानिवृत्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी भामाशाह गोपाल लाल शर्मा ने अपनी धर्मपत्नि स्व. संतोष देवी एंव अपने सुपुत्र स्व. प्रवीण कुमार की पुण्य स्मृति में लगभग 55 हजार रूपए की लागत से विधुत विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय उदयपुरवाटी में एक टिन शैड का निर्माण करवाया है। सहायक अभियंता कार्यालय नांगल में बुधवार को विद्युत विभाग के सहायक अभियन्ता मनफूलसिंह महरिया एंव सहायक राजस्व अधिकारी राजीव रोहिला के द्वारा भामाशाह गोपाल लाल शर्मा का साफा एंव माला पहनाकर अभिनन्दन किया गया। टिन शैड का भामाशाह गोपाल शर्मा ने फिता काटकर उद्घाटन किया और विभाग को सुपुर्द किया। कार्यक्रम में विधुत विभाग के सेवानिवृत कर्मचारी मंगतु राम वर्मा, ठेकेदार रविन्द्र सिंह, उपभोक्ता लिपिक नाथूराम सैनी, भामाशाह प्रेरक दलीप गुर्जर, रतनलाल सैनी सहित विधुत विभाग के अनेकों कर्मचारी उपस्थित रहें।

दिव्यांग बालकों को ट्राई साइकिल मिली

रतनगढ़ (निसं)। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बुधवाली में मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर योजना के तहत को ट्राई साइकिल वितरित की। रात्रि चौपाल में सहायता की मांग के बाद राज्य सरकार ने दोनों बालकों को ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाई। परिवार को पालनहार, पेंशन एवं राशन योजनाओं से भी जोड़ा गया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी व दीनदयाल भाटी ने बच्चों को निशुल्क दो लैपटॉप भेंट किए। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष संतोष तालनिया, अर्जुन सिंह फ्रांसा, दीनदयाल पारीक, ओम महर्षि, दीपक मुरारका, बजरंग लुहानीवाल, हेमन्त पंवार, प्रदीप पारीक सहित कई भाजपा कार्यकर्ता व गणमान्यजन उपस्थित रहे। अभिनेश महर्षि ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएलजी की बैठक आयोजित

तारानगर (निसं)। ईद-उल-जुहा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर तारानगर थाना परिसर में थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई की अध्यक्षता में बुधवार को सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई जिसमें शान्ति व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पुलिस गस्त बढ़ाने सहित कानून व्यवस्था पर चर्चा की गयी। थानाधिकारी बिश्नोई ने सभी सीएलजी सदस्यों से अपील की कि त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया जाए। अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। ईदगाह और मस्जिदों के आसपास यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। थानाधिकारी बिश्नोई ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। साइबर सेल लगातार निगरानी कर रहा है। बैठक में मौजूद सीएलजी सदस्यों और गणमान्य नागरिकों ने पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। सदस्यों ने कहा कि तारानगर में हमेशा से हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल रही है और इस बार भी ईद-उल-जुहा का पर्व मिलजुल कर मनाया जाएगा।

झुंझुनूं कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग देश के टॉप-100 कलेक्टर्स में शामिल

झुंझुनूं, (निसं)। झुंझुनूं जिले के लिए गर्व और गौरव का बड़ा क्षण सामने आया है। फेम इंडिया एवं एशिया पोस्ट द्वारा किए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में झुंझुनूं जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग को देश के शीर्ष 100 कलेक्टर्स की सूची में शामिल किया गया है।

जिले में नवाचार आधारित प्रशासन, त्वरित निर्णय क्षमता, संवेदनशील कार्यशैली और प्रभावी जनसंपर्क के दम पर डॉ. गर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर यह महत्वपूर्ण पहचान हासिल की है। देशभर के लगभग 800 जिलों में कार्यरत जिलाधिकारियों एवं जिला मजिस्ट्रेटों के कार्यों, नेतृत्व क्षमता और जनहित में किए गए प्रयासों का विस्तृत आकलन कर यह सूची तैयार की गई। विशेषज्ञों की राय, ग्राउंड रिपोर्ट्स, प्रशासनिक उपलब्धियों और मीडिया विश्लेषण के आधार पर उन

जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग

अधिकारियों का चयन किया गया जिन्होंने अपने कार्यों से जनता के बीच विश्वास और प्रशासन में नई ऊर्जा पैदा की।

फेम इंडिया और एशिया पोस्ट के अनुसार इस सर्वे में प्रशासनिक दक्षता, प्रभावी गवर्नेंस, दूरदर्शिता, नवाचार, जवाबदेही, संकट प्रबंधन, त्वरित निर्णय क्षमता, संवेदनशीलता, व्यवहार कुशलता, जनसंवाद और विकासोन्मुख सोच जैसे दस महत्वपूर्ण मानकों को आधार बनाया गया। इन सभी पैमानों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए डॉ. अरूण गर्ग ने अपनी अलग और प्रभावशाली पहचान बनाई। झुंझुनूं जिले में विकास कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग, आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसुनवाई की प्रभावी व्यवस्था ने डॉ. गर्ग को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। उनकी कार्यशैली को प्रशासनिक हलकों में भी सराहा जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा झुंझुनूं का मानः- देश के प्रतिष्ठित प्रशासनिक सर्वे में झुंझुनूं जिले का नाम शामिल होना पूरे शेखावाटी क्षेत्र के लिए सम्मान की बात मानी जा रही है। जिलेभर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सामाजिक संगठनों और आमजन ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए इसे जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है।

फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट द्वारा वर्ष 2011 से लगातार यह राष्ट्रीय सर्वे कराया जा रहा है। पिछले 15 वर्षों में यह सर्वे देश के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय प्रशासनिक आकलनों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। इसमें उन जिलाधिकारियों को स्थान दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में जनहित, सुशासन और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हों।

स्काउट एंड गाइड्स के बच्चों को जीवन विज्ञान के महत्व से अवगत करवाया

चूरू, (निसं)। अणुविभा एवं अणुव्रत समिति चूरू द्वारा समय-समय पर समाज हित में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन्हीं गतिविधियों के अंतर्गत हाल ही में स्काउट एंड गाइड्स के बच्चों को जीवन विज्ञान के महत्व से अवगत करवाया गया। अणुव्रत समिति चूरू की संरक्षिका रचना कोठारी ने बच्चों को बताया कि आज के समय में लिविंग साइंस अर्थात जीवन विज्ञान को समझना अत्यंत आवश्यक है।

जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन को कलात्मक, संतुलित एवं सार्थक ढंग से जीने की कला जीवन विज्ञान सिखाता है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे कम उम्र में ही इस विज्ञान को समझ लें तो वे भविष्य में तनाव, अवसाद एवं नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहकर आत्मविश्वास एवं सकारात्मकता के साथ जीवन जी पाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि। पावन सान्निध्य एवं निर्देशन में लाडनूं में 1 जून से 7 जून तक लेवल-1 ट्रेनर कार्यशाला आयोजित होने जा रही है। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो प्रतिभागी आगे लेवल-2 का प्रशिक्षण करना चाहें, वे 8 जून से 15 जून तक जारी कोर्स में भाग ले सकेंगे। वहीं जो प्रतिभागी केवल प्रथम चरण का प्रशिक्षण लेना चाहें, वे लेवल-1 पूर्ण करने के बाद वापस लौट सकते हैं। रचना कोठारी ने बताया कि कार्यशाला में व्यक्तित्व विकास, जीवन प्रबंधन, मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच एवं जीवन को सफल बनाने की अनेक विधियां सिखाई जाएंगी। यह प्रशिक्षण युवाओं के लिए भविष्य में आजीविका का माध्यम भी बन सकता है।

कार्यशाला का पंजीकरण शुल्क मात्र 500 रखा गया है, जबकि रहने एवं भोजन की व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। इसमें 15 वर्ष से 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। उन्होंने चूरू जिले एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक युवाओं से आग्रह किया कि वे शीघ्र पंजीकरण करवाकर इस प्रशिक्षण का लाभ लें, क्योंकि संपूर्ण भारत से प्रतिभागी इसमें शामिल होने आ रहे हैं और व्यवस्थाओं हेतु सीमित समय में रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। रचना कोठारी स्वयं इस कार्यशाला की मॉनिटरिंग में भी सक्रिय रूप से जुडी रहेंगी।

इसी अवसर पर जल संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता विषय पर भी चर्चा की गई। रचना कोठारी ने कहा कि वर्तमान समय में भीषण गर्मी एवं जल संकट को देखते हुए जल बचाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री छंतमदकतं डवकप के जल बचाओ अभियान एवं केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी ने जल संरक्षण का संकल्प लिया।

उन्होंने कहा कि वर्षा का शुद्ध जल अक्सर व्यर्थ बह जाता है, जबकि हमें अधिक से अधिक जल स्टोरेज तैयार कर वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। सरकार को ऐसे लोगों एवं संस्थाओं को सम्मानित भी करना चाहिए जो जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, ताकि समाज में प्रेरणा का वातावरण बने। रचना कोठारी ने यह भी कहा कि पुराने समय में गांवों में छोटे-छोटे जलाशय, बावडियां एवं जल संग्रहण स्थल बनाए जाते थे, जिनका उपयोग आज भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है।

यदि इन स्थानों को विकसित किया जाए तो वे बच्चों के लिए आकर्षण केंद्र, पर्यटन स्थल एवं जल संरक्षण के उत्कृष्ट उदाहरण बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि अणुविभा एवं अणुव्रत समितियां समय-समय पर जल बचाओ, बिजली बचाओ एवं सामाजिक जागरूकता से जुड़े अनेक प्रकल्प संचालित करती रहती हैं, जिनमें स्थानीय सदस्य सक्रिय भूमिका निभाते हैं।

जर्जर अंडरपास की मरम्मत के लिए फूटा जन आक्रोश

नोहर, (निसं)। क्षेत्र के हजारों रेल यात्रियों की समस्याओं के समाधान और रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर नोहर रेल विकास संघ का संघर्ष तेज हो गया है। संघ के तत्वावधान में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने महाप्रबंधक (उत्तर पश्चिम रेलवे) के नाम एक ज्ञापन नोहर स्टेशन अधीक्षक रणजीत सिंह सिंवर एवं वाणिज्य अधीक्षक सुशील आचार्य को सौंपा।

ज्ञापन में रेल प्रशासन की उदासीनता पर गहरा रोष प्रकट करते हुए सुविधाओं के विस्तार की मांग की गई। सीधी रेल सेवाओं का अभाव, जनता परेशान ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया कि नोहर क्षेत्र आज भी लंबी दूरी की रेल सेवाओं से वंचित है। बीकानेर एवं जोधपुर के लिए सीधी रेल सेवा न होने के कारण यात्रियों को सादुलपुर या हनुमानगढ़ तक की लंबी और कष्टदायक यात्रा करनी पडती है। संघ ने रेल प्रशासन के समक्ष ये मुख्य प्रस्ताव रखे है। जिनमें साबरमती-लालगढ़ रेल सेवा इसका विस्तार सादुलपुर-नोहर-हनुमानगढ़ मार्ग पर किया जाए।कोयंबटूर-जयपुर एक्सप्रेस इस ट्रेन का मार्ग बदलकर इसे सीकर-चूरू-सादुलपुर-नोहर बाया हनुमानगढ़ तक चलाया जाए।

दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन जबलपुर-निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस का विस्तार नोहर मार्ग से हनुमानगढ़ तक करने का आग्रह किया गया। जर्जर अंडरपास बना दुर्घटना का कारण संघ ने नोहर पुलिस थाने के पास स्थित अंडरपास की बदहाली पर कडी चिंता जताई। पूर्व नगरपालिका चेयरमैन श्रीराम व्यास ने कहा कि अंडरपास की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। वहां से गुजरना किसी खतरे से कम नहीं है। उन्होंने मांग की कि अंडरपास के रास्तों को अलग-अलग बनाकर इसका तत्काल पुनर्निर्माण किया जाए, ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को रोका जा सके।

नोहर रेल विकास संघ के अध्यक्ष राजकुमार जोशी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रेल प्रशासन को पहले भी कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग इन ज्ञापनों को रद्दी की टोकरी में डाल देता है। वर्तमान में ट्रेनों के संचालन का समय भी यात्रियों के लिए असुविधाजनक है और 8 घंटे के लंबे अंतराल के कारण आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पडता है। इसके साथ ही स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शेड निर्माण, पेयजल की माकूल व्यवस्था और पार्किंग चौक की मरम्मत जैसी बुनियादी समस्याओं को भी प्राथमिकता से हल करने की मांग रखी गई। ज्ञापन के समय ये रहे उपस्थित इस दौरान श्रीराम व्यास, राजकुमार जोशी, सतीश चंद्र सोनी, भैरव करवा, ख्याली राम शर्मा, रमेश कुमार सोनी, नरेंद्र सोनी, जे.के. वर्मा, राकेश नांगल, पंकज कुमार जोशी, राघव पुरोहित, नित्यम पुरोहित, भीम मिश्रा, गोरधन चाचाण, साजिद भाट्टी सहित अनेक गणमान्य नागरिक और मौजूद रहे।

पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन

हनुमानगढ़, (निसं)। ग्राम पंचायत अमरपुरा थेडी में लगातार बनी हुई पेयजल समस्या को लेकर बुधवार को वार्ड नंबर 5 और 6 के ग्रामीण वॉटर वर्क्स परिसर में एकत्रित हुए और ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से जलदाय विभाग को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में बनी बडी पानी की टंकी का पूरा लाभ सभी वार्डों को नहीं मिल रहा है, जिससे कई मोहल्लों में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है।

गांव के समाजसेवी विजेंद्र जीनागल ने बताया कि वॉटर वर्क्स में बने वाटर हेड टैंक के निर्माण को करीब दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वार्ड नंबर 5 और 6 को इससे जोड़ा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि कुछ वार्डों में ही टंकी से पानी की सप्लाई दी जा रही है, जबकि कई क्षेत्रों में आज भी पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में गांव में बोरवेल का पानी सप्लाई किया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों की मांग है कि नहर का पानी उपलब्ध करवाया जाए।

अधिकाधिक जल संरक्षण तथा नई संरचनाओं के निर्माण के निर्देश दिए

- जिला प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली

सीकर, (निसं)। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, हरियालो राजस्थान, कर्मभूमि से मातृभूमि, गिव अप अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जल स्वालंबन अभियान 2.0, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने 25 मई से 5 जून 2026 तक आयोजित होने वाले वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आमजन में जल संरक्षण के प्रति व्यापक जनजागरूकता फैलाने, अधिकाधिक जल संरक्षण संरचनाओं की साफ-सफाई कराने तथा नई संरचनाओं के निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने सीकर जिले में 31 लाख पौधारोपण के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान के अंतर्गत लगाए जाने वाले पौधों के संरक्षण एवं रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें।

जिला प्रभारी संजय शर्मा ने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत भामाशाहों के सहयोग से अधिकाधिक रिचार्ज शॉफ्ट, शॉक पिट एवं अन्य जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया। प्रभारी मंत्री ने कुसुम योजना के कंपोनेंट ए, बी एवं सी, लाडो प्रोत्साहन योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण के क्रियान्वयन कर आवश्यक निर्देश दिए।

बैठक में फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ वृहद पेयजल योजना के तहत ट्रांसफॉर्मर एवं केबल लगाकर योजना को चालू कर पानी आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पंच गौरव योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी योजनाओं में प्रगति बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। प्रभारी मंत्री ने बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।

जिले के प्रभारी मंत्री शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत टांकों एवं वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की साफ-सफाई तथा गौशालाओं में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। नगर परिषद द्वारा लगभग 15 करोड रुपये की लागत से प्रस्तावित वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की डीपीआर शीघ्र पूर्ण कर परियोजना को धरातल पर उतारने के निर्देश भी दिए।

भीषण गर्मी को देखते हुए प्रभारी मंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्युत विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने तथा विभागीय अधिकारियों एवं एफआरटी टीमों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग कर समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा। उन्होंने जिले में पेयजल की स्थिति की समीक्षा करते हुए समर कंटीजेंसी प्लान के तहत जिले में पेयजल व्यवस्था के लिए किये गए कार्यों की प्रगति, नल कनेक्शन से जलापूर्ति, टेंकरों से जलापूर्ति की समीक्षा कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने प्रभारी मंत्री को नगर परिषद के नवाचारों के तहत तैयार कपड़े के थैले, बायोडिग्रेडेबल थैले तथा गीले कचरे से निर्मित खाद सहित विभिन्न उत्पाद भेंट किए। बैठक में धोद विधायक गोरधन वर्मा ने यूआईटी क्षेत्र में नव सम्मिलित गांवों में लंबित पट्टों का शीघ्र निस्तारण करने, कृषि विभाग की फार्म पॉन्ड योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, नानी बीड़ क्षेत्र के पानी के समुचित निस्तारण, श्रम विभाग द्वारा श्रमिक पंजीयन शिविर आयोजित करने, धोद उप जिला अस्पताल को शीघ्र संचालन में लाने तथा बजट घोषणा अंतर्गत प्रस्तावित बस डिपो के लिए भूमि आवंटन जल्द करने की मांग रखी।

सार-समाचार

जल संरक्षण का संदेश दिया

पाटन (निसं)। राज्य सरकार द्वारा 25 मई से 5 जून 2026 तक चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पशुपालन विभाग नीमकाथाना द्वारा जन जागरूकता एवं स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर गोष्ठियों का आयोजन कर आमजन एवं पशुपालकों को जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।प्रांतीय तंवरावाटी गौशाला नीमकाथाना में आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी राजवीर यादव ने गौशाला अध्यक्ष नंदलाल सैनी, उपाध्यक्ष पंकज भारद्वाज एवं समस्त कार्यकारिणी की उपस्थिति में आमजन और पशुपालकों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से ही इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जा सकता है तथा जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी को सजग रहना चाहिए। गोपाल गौशाला नीमकाथाना के अध्यक्ष दौलतराम गोयल ने जल संरक्षण की शपथ दिलाते हुए पानी के अपव्यय को रोकने की अपील की। वहीं उपनिदेशक पशुपालन विभाग डॉ. आर.ए. बायला ने पौधे लगाओ, जीव बचाओ का संदेश देते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं जल बचाने के लिए प्रेरित किया।पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलदीप निठारवाल ने बताया कि आस्था जनकल्याण सेवा समिति नीमकाथाना के सौजन्य से नोडल क्षेत्र नीमकाथाना में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से पक्षियों के पीने के पानी हेतु 105 परिंडे लगाए गए, ताकि भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत मिल सके। साथ ही श्वानों के लिए एंटी रेबीज वैक्सीनेशन शिविर का भी आयोजन किया गया।कार्यक्रम में डॉ. मोहनलाल यादव, डॉ. जयपाल सिंह गुर्जर, डॉ. पंकज कुमार मंगल, वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी नरेंद्र सिंह तंवर, पशुधन निरीक्षक हंसराज यादव सहित विभागीय कार्मिकों एवं गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

जल सेवा सबसे बड़ी सेवा : जय सिंह

झुंझुनूं, (निसं)। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनूं के तत्वावधान में वंदे गंगाजल संरक्षण अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशन झुंझुनूं पर ग्रीष्मकालीन जल सेवा का आयोजन किया गया। इस दौरान महालक्ष्मी ज्वैलर्स के महासिंह मांठ एवं जयसिंह मांठ के सौजन्य से यात्रियों को ठंडा जल एवं शरबत पिलाया गया। जिसकी यात्रियों ने प्रशंसा की। सीओ स्काउट महेश कालावत ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रेलवे स्टेशन झुंझुनूं पर ग्रीष्मकालीन जल सेवा का आयोजन किया गया। जिसमें भाजपा जिला युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जयसिंह मांठ, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी झुंझुनू सुनिता यादव, जिला साक्षरता अधिकारी योगेंद्र सिंह, स्काउट जिला प्रशिक्षण आयुक्त चिरंजीलाल शर्मा ने जल सेवा करने वाले स्काउट्स गाइड्स रोवर्स रेंजर्स की हौसला अफजाई की। जल सेवा में स्वच्छ भारत संकल्प सेवा समिति के सुभाषचंद्र वर्मा, भाजपा जिला प्रवक्ता हनुमान सिंह सांखला, सुनिल कुमार रोहिल्ला, श्रीमती सुदेश एवं स्काउट विभाग से रोवर लीडर डॉ. शिवकुमार, अलसीसर स्काउट सचिव रामचंद्र मीणा, इंद्राज सिंह, राजेश कुमार, सचिव स्थानीय संघ झुंझुनूं धर्मपालसिंह, समदरलाल सैनी, रामानंद आजाद समाजसेवी एवं राष्ट्रपति स्काउट उमेश रोहिल्ला, सुरेंद्र किरोड़ीवाल, रोवर लीडर सौरव केडिया, समाजसेवी सुनिल कुमार एवं महेश कुमार, दिनेश कुमार, गिरीश जालान, जितेंद्र, संजू कुमावत, ऋतिका सहित अनेक स्काउट्स, गाइड्स ने जल सेवा में हिस्सा लेकर आमजन को ठंडा जल पिलाकर राहत प्रदान की।

परिंडो में पानी भरने का संकल्प लिया

सीकर (निसं)। श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय सीकर बुधवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (उच्च शिक्षा) के तत्वावधान में संकाय सदस्यों के साथ मिलकर परिसर में भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए परिंडे लगाकर पानी की व्यवस्था की। कॉलेज परिसर के अलग-अलग स्थानों पर परिंडे लगाए गए जिनमें महाविद्यालय स्टाफ एवं छात्राओं द्वारा नियमित रूप से आज बाँधे गए परिंडो में साफ पानी भरने का संकल्प लिया गया कार्यक्रम में करण सिंह शेखावत कहा की भीषण गर्मी में जल स्त्रोत सूख जाते हैं, ऐसे में परिंडे लगाना जीव-जंतुओं के प्रति हमारी संवेदनशीलता और नैतिक जिम्मेदारी है। रोवर लीडर राम भरोसे बैरवा ने बताया कि सेवा और प्रकृति प्रेम स्काउटिंग के मूल सिद्धांत हैं। इस पुनीत कार्य में महाविद्यालय स्टाफ एवं रोवर-रेंजर्स ने सक्रिय भागीदारी निभाई और आमजन से भी परिंडे लगाने की अपील की। प्रियंक जैन ने बताया की इस दौरान प्रोफेसर सुशीला चौधरी, प्रोफेसर सविता चौधरी, डॉ कुंभाराम महला, डॉ नरेश चेजारा, डॉ सुलोचना, डॉ अभिलाषा, डॉ राकेश कुमार, डॉ रोहित बेरवाल प्रोफेसर जुबेदा मिर्जा एवं डॉ सुरेश कुमार बंसल समाज सेविका सुनीता रेवाड़ करण सिंह शेखावत सुशील जैन प्रियंक जैन आदि उपस्थित रहे।

आरएएस में चयनित पायल का स्वागत

चूरू (निसं)। अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष नीरज रोलीवाल के नेतृत्व में जिला महामंत्री बुद्धरमल सिलक, जिला उपाध्यक्ष हरिकिशन मीषण, ओमप्रकाश जांगिड सहित अनेक समाज बंधुओं ने हाल ही में आरएएस में चयनित हुई पायल जांगिड़ का उनके निवास पर जाकर सम्मान किया तथा शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नीरज रोलीवाल ने कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में 323वीं रैंक प्राप्त कर पायल जांगिड़ ने क्षेत्र एवं समाज का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि पायल जांगिड़ ने अपने दूसरे प्रयास में यह शानदार सफलता हासिल की है, जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। जिला महामंत्री बुद्धरमल सिलक ने बताया कि पायल जांगिड़ अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिवार, विशेष रूप से अपने दादा टैगोर पब्लिक स्कूल के निदेशक सतबीर जांगिड़ तथा अपनी कड़ी मेहनत को देती हैं। साथ ही जिला सभा चूरू द्वारा साफा, श्रीफल, शॉल एवं अभिनंदन पत्र देकर पायल जांगिड़ का सम्मान किया गया, जिससे समाज में उत्साह का माहौल है।

30 मई तक 200 परिंडे लगाने का लक्ष्य

चूरू (निसं)। राजस्थान नायक समाज संयुक्त समिति जिला चूरू की ओर से चलाए जा रहे "परिंडा अभियान" के तहत गुरुवार को अग्रसेन नगर में पक्षियों के लिए परिंडों में पानी की व्यवस्था की गई। जिलाध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद नायक के नेतृत्व में समिति के पदाधिकारियों ने अग्रसेन नगर के मुख्य पार्क, शिव मंदिर परिसर व विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर मिट्टी के परिंडे लगाकर उनमें स्वच्छ पानी भरा। इस दौरान राहगीरों व स्थानीय लोगों से भी अपने घरों की छतों पर परिंडे लगाने की अपील की गई। जिलाध्यक्ष नायक ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए 24 मई से यह अभियान शुरू किया गया है। 30 मई तक 200 परिंडे लगाने का लक्ष्य है, जिसके तहत अब तक वार्ड 21, मुक्तिधाम, रेलवे कब्रिस्तान, मंगला कॉलोनी, ओम कॉलोनी व अग्रसेन नगर में परिंडे लगाए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने पर चढकर हिस्सा दिया। कार्यक्रम में तीन टीम में बनाकर अलग-अलग स्थान पर परिंडे लगाए गए। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य केवल मानव सेवा ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों की सेवा करना भी है।

कार्यशाला आज

सीकर, (निसं)। जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक विकास सिहाग ने बताया कि जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सीकर द्वारा वंदे गंगा, जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 28 मई 2026, गुरुवार को सीएसआर कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे किया जाएगा। कार्यशाला में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, उद्योग संघों के अध्यक्षों, सचिवों, प्रतिनिधियों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीएसआर के माध्यम से जल संरक्षण गतिविधियों में सहभागिता बढाना, जल संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना तथा अभियान को जन-जन तक पहुंचाना है। कार्यशाला में जल संरक्षण के महत्व, सीएसआर फंड के प्रभावी उपयोग तथा अभियान के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

नवनिर्मित कुएं का उद्घाटन

चिड़ावा, (निसं)। भाजपा नेता राजेश दहिया ने चिड़ावा के वार्ड न 38 में नवनिर्मित कुएं का उद्घाटन किया। दहिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व जल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए ।

NAME CHANGE

में पूर्ण मल हरिजन पुत्र स्व. भागीरथ मल वर्मा निवासी मु. पो. दायरा, वाया-खण्डेला, जिला-सीकर पिन-332709, मैंने अपना नाम पूर्ण मल हरिजन से पूर्ण मल वर्मा में बदल लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

चौमूं : टेम्पो क्रूजर गाड़ी व ट्रक में भिड़ंत, महाराष्ट्र के तीन श्रद्धालुओं की मौत, नौ घायल

महाराष्ट्र के श्रद्धालु टेम्पो क्रूजर गाड़ी में सवार होकर खाटूश्यामजी जा रहे थे

चौमूं/कालाडेरा, (निसं)। चौमूं शहर से गुजरने वाले जयपुर-सीकर नेशनल हाईवे 52 पर बुधवार को आगे चल रहे एक ट्रक में टेम्पो क्रूजर गाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस टक्कर में टेम्पो क्रूजर गाड़ी में सवार महाराष्ट्र के तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई,

- चौमूं शहर से गुजरने वाले जयपुर-सीकर नेशनल हाईवे 52 पर हुआ हादसा, ट्रक से टकराने के बाद क्रूजर गाड़ी सड़क किनारे बने होटल-रेस्टोरेंट में घुस गई
- चौमूं शहर के निजी अस्पताल पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भर्ती घायलों की कुशलक्षेम पूछी

जबकि नौ लोग घायल हो गए। ट्रक से टकराने के बाद क्रूजर गाड़ी सड़क किनारे बने होटल-रेस्टोरेंट में घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि क्रूजर के परखच्चे उड़ गए। होटल के बाहर खड़ी एक और कार से टेम्पो क्रूजर गाड़ी टकराने के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

जानकारी के अनुसार दुर्घटना बुधवार सुबह करीब सात बजे चौमूं शहर से गुजरने वाले हाइवे के पास स्थित स्टेडियम के पास ब्यावरिया कट एवं हाडौता पुलिया (वीर हनुमान पुलिया) के पास हुई। तीनों शवों को चौमूं के सरकारी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं।

चौमूं पुलिस थानाधिकारी हरबेन्द्र सिंह ने बताया कि महाराष्ट्र के श्रद्धालु टेम्पो क्रूजर में सवार होकर खाटूश्यामजी (रिंगस, सीकर) जा रहे थे। चौमूं शहर से गुजरने वाले हाइवे पर आगे चल रहा ट्रक अचानक लेफ्ट साइड में जाने के लिए मुड़ा। इसी दौरान पीछे से आ रही टेम्पो क्रूजर गाड़ी, ट्रक में घुस गई। क्रूजर गाड़ी रितेश (22) चला रहा था। क्रूजर में सवार शालू बाई (75), मेघा (40), आदेश (18) की मौके पर ही मौत हो गई। ये सभी परभणी (महाराष्ट्र) के गंगाखेड़ इलाके के हरंगुल के रहने वाले थे। इसके अलावा नौ लोग घायल हुए हैं। सभी घायल परभणी (महाराष्ट्र) के नानलपेथ के रहने वाले हैं। हादसे कि सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से नजदीक के अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटवाकर ट्रैफिक सुचारू करवाया गया। हादसे में घायल गीता देवधर पुत्री सुनील राव, गायत्री देवधर पुत्री सुनील राव, खुशी जावड़े पुत्री बालासाय, अंकिता पुत्री रमेश, रितेश पुत्र अनिल, ऋषिकेश पुत्र अनिल, शकुंतला पत्नी अशोक, सुनीता पत्नी सुरेश, यशोदा पत्नी रमेश घायल हुए है। टेम्पो क्रूजर गाड़ी महाराष्ट्र नंबर की है। ट्रक और टेम्पो क्रूजर गाड़ी जयपुर से सीकर की ओर जा रहे थे।

वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने खाटूश्यामजी जा रहे वाहन के सीकर बायपास हाड़ोता के पास बावरिया कट पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसमें सवार गांव हरगुण्ड, जिला परबनी, महाराष्ट्र के मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल को बुधवार शाम जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली वह लोकभवन से चौमूं स्थित आर.के. फ्रैक्चर हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर के लिए रवाना हुए और वहां भर्ती घायलों की उन्होंने कुशलक्षेम पूछी। उन्होंने घायलों के अच्छे इलाज के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने दुर्घटना में घायल लोगों के प्रति सहानुभूति जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

हादसे के बाद टेम्पो क्रूजर गाड़ी होटल में घुस गई।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने चौमूं जाकर घायलों के हाल जाने।

चूरू एसपी ऑफिस से किडनैप की गई युवती बरामद

- दो आरोपी गिरफ्तार, एसपी ऑफिस के तीन कमांडो और एक ड्राइवर निलंबित

चूरू, (निसं)। एसपी कार्यालय के स्वागत कक्ष से अपहरण की गई युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। युवती पूरी तरह सुरक्षित है। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना की जांच प्रभावित नहीं हो, इसके लिए एसपी निश्चय प्रसाद एम ने एसपी कार्यालय में तैनात 3 कमांडो और एक ड्राइवर को निलंबित कर दिया है।

एसपी निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि 25 मई को कुछ लोग एसपी कार्यालय के स्वागत कक्ष से युवती को जबरन उठाकर ले गए थे। इस संबंध में झाड़सर निवासी कृष्ण कुमार ने किडनैप का मामला दर्ज कराया था। कृष्ण कुमार युवती के साथ सुरक्षा की गुहार लगाने एसपी कार्यालय आए थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने 4 टीमें गठित की और विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मंगलवार देर रात पुलिस ने लूणकरणसर से युवती को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। इस कार्रवाई में चूरू कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया और सीआई संदीप पूनिया की टीम की अहम भूमिका रही। पुलिस ने युवती के बयान के बाद उसको स्वेच्छा से उसके पति के साथ भेज दिया गया है।

चूरू में नौतपा के तीसरे दिन पारा 46 डिग्री पार

चूरू, (निसं)। जिले में नौतपा के तीसरे दिन भीषण गर्मी ने अंचल में हड़कंप मचा दिया। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दोपहर ढ़ाई बजे तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि प्रात: 11:30 बजे यह 43 डिग्री सेल्सियस था। तेज लू के कारण शहर की सड़कों पर आवाजाही कम रही।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में चल रहे हीटवेव और तीव्र हीटवेव का दौर आगामी दो-तीन दिनों तक जारी रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। बीकानेर, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 27 और 28 मई को अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। हालांकि, एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 28 मई से राज्य के कुछ भागों में आंधी-बारिश हो सकती है। आंधी-बारिश की गतिविधियों में 30 मई से और बढ़ोतरी होने की संभावना है, और जून के पहले सप्ताह में भी कुछ भागों में यह गतिविधियां जारी रह सकती हैं।

आरएएस भर्ती-2026 का विज्ञापन जारी, 607 पदों पर होगी भर्ती

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से प्रारंभ होगी

अजमेर, (निसं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य सेवाओं के 192 पदों तथा अधीनस्थ सेवाओं के 415 पदों सहित कुल 607 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है।

आयोग सचिव ने बताया कि भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 से प्रारंभ होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वर्गवार पदों का वर्गीकरण, आवेदन शुल्क, आरक्षण नियम, परीक्षा योजना एवं आवेदन प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी गई है।

आयोग के अनुसार भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होगी, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक स्वरूप में आयोजित की जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्व में 9 जनवरी 2026 को जारी प्रेस नोट के माध्यम से जारी किया जा चुका है और उसी निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से पाठ्यक्रम डाउनलोड कर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं।

आरपीएससी ने यह भी बताया कि परीक्षा तिथि एवं परीक्षा केंद्रों की जानकारी यथासमय अलग से जारी की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने तथा अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने की अपील की है।

जोधपुर में साधारण मूंगफली से नकली बीज बनाने की दो फैक्ट्रियां पकड़ी

50 करोड़ रुपये मूल्य का संदिग्ध मूंगफली बीज और कच्चा माल बरामद

जोधपुर, (कासं)। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चौमूं के गोविन्दगढ़ और सीकर में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई के बाद कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा का काफिला बुधवार को अचानक जोधपुर पहुंचा। यहां के कृषि और औद्योगिक हल्कों में उस समय हड़कंप मच गया, जब खुद कृषि मंत्री ने बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित बीज निर्माण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा।

- कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित बीज निर्माण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारा
- मौके पर दस चक्का ट्रक खड़ा मिला, जिसमें घटिया और गैर-कानूनी तरीके से तैयार किए गए मूंगफली बीज की बोरियां भरी जा रही थीं
- दूसरी फैक्टरी में मंत्री के आने की भनक मिलते ही मुख्य संचालक और मालिक परिसर को खुला छोड़कर फरार हो गये, फैक्टरी को सील किया

जोधपुर सर्किट हाउस से बुधवार सुबह जैसे ही कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ, पूरे शहर के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई। विभागीय अधिकारियों से प्राप्त प्राथमिक विवरण के अनुसार, कृषि विभाग को पिछले लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ शातिर अवैध बीज कारोबारी खुले बाजार से कम दाम पर साधारण खाने वाली वाणिज्यिक मूंगफली की खरीद करते हैं। इसके बाद बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाणीकरण, बिना ग्रेडिंग और बिना आवश्यक रासायनिक उपचार के, उस साधारण मूंगफली को चमकीली थैलियों और ब्रांडेड बोतलों में पैक करके महंगे और उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज के रूप में किसानों को बेचकर करोड़ों रुपये का अवैध मुनाफा कमा रहे हैं। बुधवार को जब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक कोल्ड स्टोरेज और संबंधित फैक्ट्रियों पर छापा मारा, तो वहां इस काले कारोबार की लाइव तस्वीरें देखकर अधिकारी भी दंग रह गए। मौके पर एक बड़ा दस चक्का ट्रक खड़ा मिला, जिसमें इस घटिया और गैर-कानूनी तरीके से तैयार किए गए मूंगफली बीज की बोरियां भरी जा रही थीं।

कृषि मंत्री द्वारा एक साथ दो बड़ी फैक्ट्रियों पर की गई इस कार्रवाई का नतीजा बेहद चौंकाने वाला रहा। पहली फैक्टरी के भीतर जब विभाग की टेक्निकल टीम ने दस्तावेजों, लाइसेंस और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया, तो वहां भारी विसंगतियां पाई गईं। फैक्टरी के भीतर बिना किसी वैध रिकॉर्ड के अवैध रूप से डंप किया गया करीब 50 करोड़ रुपये मूल्य का संदिग्ध मूंगफली बीज और कच्चा माल पाया गया, जिसे मंत्री मीणा ने तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश दे दिए। वहीं, जब प्रशासनिक अमला दूसरी फैक्टरी के परिसर में पहुंचा, तो वहां हड़कंप का माहौल था। मंत्री के आने की भनक मिलते ही दूसरी फैक्टरी का मुख्य संचालक और मालिक परिसर खुला छोड़कर मौके से फरार होने में सफल रहा। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मालिक की अनुपस्थिति के बावजूद पूरी फैक्टरी को अभी सील कर दिया जाए और पुलिस सुरक्षा तैनात की जाए ताकि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके।

कार्रवाई पूरी होने के बाद मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों और किसानों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बेहद कड़े और सपाट शब्दों में अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के सीधे-साधे किसानों की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले ऐसे माफियाओं को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि आज जब्त किए गए 50 करोड़ के इस पूरे स्टॉक के सैंपल तुरंत सरकारी लैबोरेट्री में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जैसे ही लैब की रिपोर्ट में मिलावट या गैर-प्रमाणित होने की पुष्टि होगी, इन दोनों फैक्ट्रियों के मालिकों और इनके पूरे नेटवर्क के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर इन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा।

नोखा के सहकारी बैंक में 2.90 करोड़ के गबन का आरोप

नोखा, (निसं)। बीकानेर के दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की नोखा शाखा में करीब 2 करोड़ 90 लाख 92 हजार रुपए के गबन का मामला सामने आया है। वर्तमान शाखा प्रबंधक रवि मीणा ने नोखा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पुलिस ने इस मामले में पूर्व शाखा प्रबंधक ताराचंद बोथरा, सेवानिवृत्त ऋण पर्यवेक्षक चैनाराम गौरा, जसरासर शाखा में पदस्थापित बैंकिंग सहायक रामस्वरूप सोनी, बैंकिंग सहायक मूलचंद गोदारा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने आपसी सांठगांठ कर बैंक में जमा ग्राहकों की मियादी जमाओं (एफडीआर) और अन्य खातों का दुरुपयोग किया। इससे करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता की गई। यह भी आरोप है कि पूर्व शाखा प्रबंधक ताराचंद बोथरा ने अपने बेटों महेंद्र बोथरा और शांतिलाल बोथरा को संविदा पर नियुक्त कर बैंक के ऑनलाइन कार्य करवाए। आरोपियों ने विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों और खाताधारकों की एफडीआर को बिना अधिकार समयपूर्व तोड़कर राशि अन्य खातों में ट्रांसफर की। कई मामलों में बैंक रिकॉर्ड में संबंधित वाउचर भी उपलब्ध नहीं मिले।

प्रार्थी रवि मीणा ने बताया कि बैंक ने इस मामले में अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, बीकानेर खंड में वाद दायर किया था। न्यायालय ने 21 अप्रैल 2026 को दिए अपने निर्णय में तत्कालीन शाखा प्रबंधक ताराचंद बोथरा, चैनाराम गौरा और रामस्वरूप सोनी को दोषी माना था। उनके खिलाफ वसूली के आदेश भी पारित किए गए थे।

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नोखा तहसील क्रय-विक्रय सहकारी समिति के खातों का उपयोग गबन के लिए किया गया। करोड़ों रुपए विभिन्न खातों और एफडीआर में स्थानांतरित किए गए। पुलिस के अनुसार, रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी एसआई कुशलाराम ने बताया कि मामले में बैंक रिकॉर्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और संबंधित खातों की गहन जांच की जाएगी।

सिंघाना में अवैध शराब सहित कंटेनर जब्त

सिंघाना, (निसं)। पुलिस थाना सिंघाना ने हरियाणा निर्मित 228 कार्टून अंग्रेजी शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त किया है। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार चालक की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार बुधवार को कांस्टेबल आनंद कुमार एवं रमेश कुमार ने सूचना दी कि एक संदिग्ध कंटेनर में अवैध शराब होने की आशंका पर उसे रुकवाया गया है, लेकिन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कंटेनर की तलाशी ली।

झुंझुनूं में 10 के नए नोट की गड्डी के नाम पर करोड़ों की ठगी

- सर्राफा कारोबारी से 21 लाख हड़पे, पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज

झुंझुनूं, (निसं)। शहर में 10 रुपए के नए नोटों की गड्डी सस्ते में देने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। कोतवाली थाना पुलिस ने वार्ड-33 खोरा मोहल्ला निवासी सर्राफा कारोबारी मुस्तफा की रिपोर्ट पर पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

पीड़ित मुस्तफा पुत्र हाजी अब्दुल सत्तार ने बताया कि उसकी रोड नंबर 3 पर सोने-चांदी की दुकान है। इस्लाम नगर बाकरा रोड निवासी इब्राहिम पुत्र अब्दुल सलीम से उसकी पुरानी जान-पहचान थी। इब्राहिम ने बताया कि वह रोडवेज बस स्टैंड के सामने संगम होटल के नीचे किराना दुकान चलाने वाले राघव भीमसरिया से 10 के नए नोट की गड्डी 1050 रुपए में लेकर 1100 में बेचता है। दिसंबर 2025 में इब्राहिम, उसके पिता अब्दुल सलीम, अदरीश उर्फ मिंडा, मकबूल मणियार और राघव भीमसरिया ने मुस्तफा को इस काम में जोड़ लिया। पहले पांच लाख एडवांस लेकर पांच लाख की गड्डियां दे दी। जिससे भरोसा बन गया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया है कि 27 दिसंबर 2025 को चारों आरोपी दुकान पर आए और कहा कि राघव को 21 लाख एडवांस देने हैं। पांच-सात दिन में रुपए या गड्डी लौटाने का वादा कर मुस्तफा से 21 लाख रुपए ले लिए। बाद में टालमटोल करते रहे और रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। मुस्तफा जब अरबाज कायमखानी के साथ तकादा करने गया तो इब्राहिम, सलीम, मकबूल और अदरीश ने कहा कि हमारा तो लोगों को गड्डी का झांसा देकर रुपए हड़पने का ही काम है। भाग जाओ वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। अदरीश ने कबूला कि राघव से इब्राहिम को उसने ही मिलवाया था। मुस्तफा की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने इब्राहिम, अब्दुल सलीम, मकबुल, अदरीश उर्फ मिंडा और राघव भीमसरिया के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित का आरोप है कि इब्राहिम और सलीम रुपए लेकर विदेश भागने की फिराक में हैं।

पीड़ित को पता चला कि गैंग ने शाहरुख से 64.32 लाख, महमूद काजी से 33 लाख, अनवर मणियार से 18.50 लाख, समीर से 15 लाख, खादिम से 15 लाख, साजिद से 14.50 लाख, सोनू खान से 12 लाख रुपए इसी तरह ठगे हैं। सभी को गड्डी देने का झांसा दिया गया था।

हथियार सहित चार बदमाश गिरफ्तार

सादुलपुर, (निसं)। राजगढ़ पुलिस व डीएसटी टीम चूरू ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कस्बे में बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे 4 शातिर बदमाशों को अवैध लोडेड हथियारों के साथ दबोच लिया। पुलिस की तत्परता से वारदात से पहले ही आरोपियों के मंसूबों पर पानी फिर गया।

26 मई को आसूचना अधिकारी कर्मपाल कानि. को सूचना मिली कि बिजली बोर्ड राजगढ़ के पास 3-4 संदिग्ध युवक हथियारों के साथ घूम रहे हैं। जिस पर थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग मर विक्रमसिंह सउनि के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी की। जिसमें पुलिस को देख बाइक से भागने की कोशिश कर रहे चारों को पुलिस टीम ने दबोच लिया। तलाशी में रोहित उर्फ मेन्टल के पास से 3 कारतूस वाली लोडेड देशी पिस्टल, राहुल के पास से 2 कारतूस वाली लोडेड पिस्टल और दीपक उर्फ संदीप के पास से 2 जिंदा कारतूस मिले। चौथा आरोपी अमित है।

भरतपुर में 10 हेक्टेयर में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को ग्राम खडेरा और सेवर कला में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में की गई अवैध प्लॉटिंग को हटाते हुए लगभग 90 भूखंडों की बाउंड्री वॉल और ग्रेवल सड़कें तोड़ी गईं।

- अवैध प्लॉटिंग को हटाते हुए लगभग 90 भूखंडों की बाउंड्री वॉल और ग्रेवल सड़कें तोड़ी

भरतपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों को जेसीबी से तोड़ने की कार्रवाई की।

भरतपुर विकास प्राधिकरण के तहसीलदार, पश्चिमी ज़ोन, मनीष कुमार मीना ने बताया कि बीडीए क्षेत्राधिकार में कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति के अवैध प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। इसके खिलाफ प्राधिकरण लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उसी आज ग्राम खडेरा और सेवर कला में विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया।

कार्रवाई के दौरान करीब 10 हेक्टेयर भूमि में किए गए अवैध निर्माण हटाए गए और लगभग 90 भूखंडों की बाउंड्री वॉल व ग्रेवल सड़क को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। तहसीलदार मनीष कुमार मीना ने कहा कि बीडीए द्वारा अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही अपनी भूमि पर प्लॉटिंग का कार्य करें। उन्होंने भूखंड खरीदने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी भूमि को खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि उस भूमि का लेआउट भरतपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित है या नहीं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कार्रवाई के दौरान मौका मजिस्ट्रेट मनीष कुमार मीणा, तहसीलदार (पश्चिमी जोन), मुकेश कुमार, तहसीलदार (पूर्वी जोन), सहायक अभियंता मनोज पाराशर, भू-अभिलेख निरीक्षक ज्ञान सिंह निमेश, दीवान सिंह तथा पटवारी मृत्युंजय मिश्रा, दिगंबर सिंह और लोकेश शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे।

युवक की मौत

करौली, (निसं)। जिले के मंडरायल में स्थित नींदर बांध में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से मंडरायल के साईंबाबा निवासी उस्मान खान की मौत हो हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अपने मित्रों के साथ बांध में नहाने गया था। नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूब गया। सूचना मिलने पर ग्रामीणो ने पहुंचकर साथियों के साथ युवक को अचेत अवस्था बांध के पानी से निकालकर मंडरायल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर शव परिवार जन को सुपुर्द किया।

टोंक में गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। अवैध बजरी खनन व परिवहन के विरूद्ध अलग-अलग थानों में पुलिस टीमों ने कार्यवाही की। जिला स्पेशल टीम व थाना डिग्गी पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत संयुक्त कार्यवाही करते हुए लगभग डेढ़ लाख रुपए कीमत का 2.964 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपी जितेन्द्र पुत्र रामेश्वर सेनी निवासी खातियों का मोहल्ला चान्दसेन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ थाना डिग्गी में एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर मामला दर्ज किया गया है।

इसी क्रम में पुलिस थाना बरोनी टीम ने अवैध बजरी खनन व परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये ग्राम ककराज स्थित बनास नदी में अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुये तीन टैक्टर-ट्रॉली जो 24 टन अवैध बजरी से भरे हुए को जब्त कर चालक व मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

इसी प्रकार पुलिस थाना झिराना टीम ने भी अवैध बजरी परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये ग्राम सौंदीफल में अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुये एक टैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया। इसी प्रकार वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के निवाई पुलिस थाना टीम ने पूर्व में दर्ज अवैध बजरी खनन व परिवहन के प्रकरण में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

5 सीमावर्ती जिलों के 184 गांवों में 3-3 करोड़ रु. के विकास कार्य होंगे

सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे वाईब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम-II की निरंतर मॉनिटरिंग

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। वाईब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम-II के तहत राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिलों के 184 रणनीतिक गांवों में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, टेलीविजन, दूरसंचार कनेक्टिविटी, आजीविका सृजन, पर्यटन, संस्कृति, जागरूकता गतिविधियों को प्रोत्साहन, युवा सशक्तीकरण एवं कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, सहकारिता, स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पाद संगठनों का विकास एवं परिसंपत्तियों के रखरखाव सहित ग्राम अवसंरचना से जुड़े व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे। इन प्रयासों से सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर तो होगा ही, साथ ही रोजगार, पर्यटन, स्थानीय आजीविका और सामाजिक सशक्तीकरण के नए अवसर भी विकसित होंगे।

प्रदेश के श्रीगंगानगर के 68, बीकानेर के 46, बाड़मेर के 36, जैसलमेर के 30 और फलौदी जिले के 4 गांवों को कार्यक्रम के तहत रणनीतिक गांवों के रूप में चयनित किया गया है। वर्तमान में वाईब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II के अंतर्गत चयनित कुल 184 में से 123 गांवों में 232 करोड़ से अधिक की लागत के 515 कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच और "सीमावर्ती गांव देश के अंतिम नहीं, बल्कि प्रथम गांव हैं" की भावना को साकार करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की नई तस्वीर गढ़ने जा रही है।

- **मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम से सीमावर्ती गांवों के विकास को मिली रफ्तार**

कार्यक्रम के अनुसार राज्य के रणनीतिक गांवों में विकास एवं योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम के अनुसार राजस्थान के सीमा ब्लॉकों के 3 हजार 195 गांवों में सभी मौसम में 4 थीमेटिक क्षेत्रों की संतृप्ति के तहत सडक संपर्क, दूरसंचार कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी के साथ-साथ ऑन ग्रिड विद्युतीकरण किया जाएगा। वहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के निकट रहने वाले समुदायों के साथ जुड़ाव बढ़ाने, विश्वास स्थापित करने एवं सकारात्मक संबंध विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामुदायिक बैठकों, पर्यटन गतिविधियों, प्रशिक्षण सत्रों तथा जागरूकता अभियानों के आयोजन के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से संवेदनशील एवं भावनात्मक जुड़ाव और अधिक मजबूत किया जा रहा है।

कार्यक्रम के तहत अब तक 10 क्षेत्रों में संतृप्ति के लिए चयनित राजस्थान के समस्त 184 रणनीतिक गांवों का सत्यापन एवं प्रोफाइल अपडेशन किया जा चुका है। वहीं, 4 थीमेटिक क्षेत्रों में संतृप्ति हेतु सीमा ब्लॉक के कुल 3 हजार 195 गांवों में से 3 हजार अधिक गांवों का सत्यापन एवं 2 हजार 558 गांवों का प्रोफाइल अपडेशन किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार बजट घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत 5 सीमावर्ती जिलों के 1 हजार 206 गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिवर्ष 150 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025-26 में योजना के तहत बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, खेल, पर्यटन, आधारभूत संरचना विकास से जुड़े 137 करोड रुपये की लागत के 1 हजार से अधिक कार्यों को स्वीकृति दी गई है।

इस मानसून में 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा राज्य सरकार ने

"हरियालो" एप से होगी पौधों की जियो-टैगिंग और पूर्व में लगाये गये पौधों की पुष्टि

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेकर मिशन हरियालो राजस्थान की तैयारियों पर चर्चा की।

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में बुधवार को मिशन हरियालो राजस्थान की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मानसून 2026 के दौरान प्रदेशभर में किए जाने वाले वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों एवं पूर्व वर्षों में लगाए गए पौधों के सत्यापन कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग लगाए गए पौधों की जीवित्तता को भी सुनिश्चित करें। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में भी पौधारोपण को प्राथमिकता से करने के लिए कहा।

उन्होंने बताया कि मानसून 2024 में 7.22 करोड़ तथा मानसून 2025 में 11.75 करोड से अधिक पौधारोपण कर राज्य ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। आगामी मानसून 2026 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पौधारोपण के साथ पौधों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए हरियालो ऐप के माध्यम से पौधों की जियो-टैगिंग एवं लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही मुख्य सचिव ने हरियालो राजस्थान वेबपोर्टल एवं मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।

जैन समाज ने भाजपा से मांगी राज्यसभा प्रत्याशी की सीट

सुनील कोठारी को अवसर दिए जाने का आग्रह किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा के लिए संभावित प्रत्याशी को लेकर बुधवार शाम को जैन समाज के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की। यह मुलाकात सकल जैन समाज जयपुर के तत्वावधान में समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा की गई। इसमें श्री महावीरजी अतिशय क्षेत्र, राजस्थान जैन सभा, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, श्री जैन श्वेताम्बर संघ, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सभा, अनुविभा जयपुर केंद्र, श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक संघ और जैन विश्व भारती आदि संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

प्रतिनिधिमंडल ने मदन राठौड़ के समक्ष जैन समाज की भावनाओं को रखते हुए आग्रह किया कि वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा में जैन समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अत: समाज को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए जैन समाज से किसी योग्य प्रतिनिधि को राज्यसभा भेजा जाए। बैठक में प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी और भूपेंद्र सैनी भी विशेष रूप से उपस्थित थे। जैन समाज की ओर से वरिष्ठ नेता सुनील कोठारी को अवसर दिए जाने का आग्रह किया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि सुनील कोठारी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के समर्पित, सक्रिय एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने संगठन में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर भी कार्य किया है। पार्टी संगठन, वैचारिक प्रतिबद्धता तथा जनसंपर्क के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। वर्ष 2019 एवं 2024 के लोकसभा चुनावों में जयपुर संसदीय क्षेत्र से उनका नाम भाजपा प्रत्याशी के रूप में गंभीरता से विचाराधीन रहा। अंतिम समय में संगठनात्मक परिस्थितियोंवश अन्य प्रत्याशियों को अवसर दिया गया, तथापि कार्यकर्ताओं एवं समाज के मध्य उनकी स्वीकार्यता निरंतर बनी हुई है। प्रतिनिधिमंडल में जैन समाज से सुधांशु कासलीवाल, विवेक काला, राजकुमार बराडिया, सुभाष जैन, हितेश भाण्डिया, अमित हिरावत, ज्योति कोठारी, विनोद कोटखावदा, अमिताभ हीरावत, नितिन दुगड़, प्रवीण मेहता, राजेंद्र बांठिया, सरदारसिंह बोथरा, सुभाष जैन, सुनील बख्शी, सुनील जैन, सुनील मुनोत, सुरेश कोठारी, गौरव मांडोत, कमल सचेती और रजत डागा उपस्थित रहे।

जैन समाज के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की।

एक जून से राजस्थान में चलेगा "उमंग" अभियान

जयपुर। राजस्थान में बालश्रम, बाल बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ राजस्थान पुलिस 1 जून से 30 जून तक राज्यव्यापी विशेष अभियान उमंग- चलाएगी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य बाल शोषण रोकना और पीड़ित बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सिविल राइट्स एवं एएचटी) हवासिंह घुमरिया ने प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को अभियान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हर जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।इस अभियान के तहत होटल, ढाबे, फैक्ट्रियां, ईंट भट्टे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल और हाईवे किनारे स्थित क्षेत्रों में बच्चों की विशेष स्क्रीनिंग की जाएगी। पुलिस थानेवार रेस्क्यू टीमें गठित की जाएंगी, जिनमें पुलिसकर्मियों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, बाल अधिकारिता विभाग और एनजीओ प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। रेस्क्यू किए गए बच्चों का मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा और उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया जाएगा। अन्य राज्यों से लाए गए बच्चों के मामलों में संबंधित राज्यों की पुलिस को भी सूचना दी जाएगी।

'विधि शिक्षा का उपयोग जरूरतमंदों, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें'

डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि विधि शिक्षा प्रत्यक्षत: समाज से जुड़ी शिक्षा है। इसका उपयोग विद्यार्थी जरूरतमंदों, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने विधि शिक्षा में राष्ट्र और समाज हितों को सदा अग्रणी रखने और इस शिक्षा में उच्च संवैधानिक मूल्यों के साथ राजस्थान को अग्रणी किए जाने का आव्हान किया। बागडे बुधवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में सम्बोधित कर रहे थे।

- **समारोह में राज्यपाल बागड़े, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री बैरवा ने पदक एवं डिग्रियां प्रदान की**

राज्यपाल ने डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करते हुए कहा कि बॉम्बे विधानसभा में वर्ष 1938 में उन्होंने कहा था कि "मैं चाहता हूं कि समस्त लोग पहले भारतीय हों, और अंतत: भारतीय हों तथा भारतीय के सिवाय और कुछ भी नहीं हों। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा का भी मूल यही होना चाहिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद किसी वर्ग, जाति या समुदाय से आते हैं। देश सवोच्च है।"

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि डॉ. अंबेडकर विधि विशेषज्ञ ही नहीं थे वह बहुत बड़े अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, लेखक और विविध विषयों के जानकार थे। वह 1927 में बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य बन गए थे। उन्होंने कहा कि देश के पहले कानून मंत्री डॉ. अंबेडकर थे।

समारोह में राज्यपाल बागडे, केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल और उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विद्यार्थियों को डिग्री और पदक प्रदान किए।

राज्यपाल श्री बागडे ने दीक्षा प्राप्त 25 हजार से अधिक विद्यार्थियों की डिग्रियां डिजी लॉकर में कंप्यूटर का बटन दबाकर लाइव की। इससे पहले कुलगुरु डॉ. निष्ठा जसवाल ने स्वागत उद्बोधन में विश्वविद्यालय की उपलब्धियां के बारे में विस्तार से बताया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने बुधवार को डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया।

पुलिस कमिश्नर 30 मई को करेंगे जनसुनवाई

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल 30 मई को दोपहर 11.30 से 01.30 बजे तक पुलिस थाना चित्रकूट पर जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान वैशाली नगर सर्किल के वैशाली नगर, करणी विहार एवं चित्रकूट थानों के परिवादियों की जनसुनवाई की जावेगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुँचाना है।

हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर से मारपीट करने वाली मां-बेटियां गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल में संचालक डॉक्टर से मारपीट और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने मां और दो बेटियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी युवती पहले अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत थी और पूर्व में डॉक्टर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने के बाद समझौते के जरिए रकम वसूल चुकी थी। बाद में दोबारा पैसों की मांग करने पर विवाद हुआ और मारपीट की वारदात हुई।पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि मानबाग स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल के संचालक जितेन्द्र कुमार मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 अप्रैल 2026 को तीन महिलाएं जबरन उनके निजी केबिन में घुस आईं और पैसों की मांग करने लगीं। विरोध करने पर महिलाओं ने गाली-गलौज करते हुए डॉक्टर के साथ लात-घूंसों और चप्पलों से मारपीट की। घटना में डॉक्टर घायल हो गए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीरज पाठक एवं एसीपी आमेर सुरेंद्र सिंह राणावत के निर्देशन में जयसिंहपुरा खोर थानाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजना महावर, उसकी बहन ज्योति महावर और मां रेखा देवी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों गलता गेट क्षेत्र की निवासी हैं।पुलिस जांच में सामने आया कि संजना महावर पहले इसी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ थी। वर्ष 2023 में उसने डॉक्टर के खिलाफ सिंधीकैंप थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। बाद में समझौता कर कोर्ट में बयान बदल दिए गए थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने समझौते के दौरान डॉक्टर से रकम ली थी। इसके बाद 28 अप्रैल को दोबारा पैसे मांगने अस्पताल पहुंचीं। डॉक्टर द्वारा मना करने पर उन्होंने मारपीट कर दी।

पीएचईडी का वरिष्ठ रसायनज्ञ सेवा से हटाया जाएगा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध 4 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति दी है। भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन अधिनियम, 2018) के तहत दोष सिद्धि के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को सेवा से पदच्युत करने का भी अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ रसायनज्ञ को पेयजल के नमूनों की गुणवत्ता जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के अपराध में सेवा से हटाने का निर्णय लिया है। साथ ही, एक अन्य प्रकरण में दोषी अधिकारी को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी है।

उन्होंने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध संचालित 14 जांच प्रकरणों में पेंशन रोकने तथा 2 सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध 16 सी.सी.ए. की जांच कार्यवाही में वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार सी.सी.ए. नियम 23 एवं 34 के तहत प्रस्तुत अपील एवं रिव्यू याचिका के 7 प्रकरणों को खारिज करते हुए पूर्व में दिए गए दण्ड को यथावत रखा है।

एसएमएस अस्पताल में महिला से अभद्रता

जयपुर। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। अस्पताल के गेट नंबर-3 के पास देर रात एक महिला से अभद्रता और धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक नशेड़ी युवक ने उससे जबरन शादी करने का दबाव बनाया और मना करने पर गोली मारने की धमकी दी। घटना स्थल से एसएमएस थाना की दूरी करीब 100 मीटर बताई जा रही है।

- **शादी का दबाव बनाकर गोली मारने की धमकी दी**

जानकारी के अनुसार महुआ क्षेत्र निवासी महिला पिछले चार दिनों से अपने बीमार परिजन के उपचार के लिए अस्पताल में रुकी हुई थी। बुधवार देर रात करीब दो बजे वह अस्पताल परिसर में अकेली थी, तभी एक युवक उसके पास पहुंचा और अभद्रता करते हुए शादी करने का दबाव बनाने लगा। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर गोली मारने की धमकी दी। घटना से सहमी महिला ने पूरी रात अस्पताल परिसर के दूसरे हिस्से में छिपकर बिताई।पीड़िता ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से अस्पताल परिसर में कुछ असामाजिक तत्व उसे परेशान कर रहे थे। उसने इस संबंध में सुरक्षा गार्डों को भी जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। महिला ने बताया कि घटना के दौरान उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई सुरक्षाकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा।

घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। मरीजों के परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि रात के समय कई सुरक्षा गार्ड ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन पर रील देखने और सोशल मीडिया चलाने में व्यस्त रहते हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर में देर रात नशेड़ियों और संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है तथा चोरी और अभद्रता की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस और अस्पताल प्रशासन की ओर से जांच की जा रही

गबन-भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में हो कड़ी कार्रवाई : मंत्री गौत्तम दक

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने विभाग में अनियमितताओं, गबन व भ्रष्टाचार के दर्ज प्रकरणों में कठोर कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग, पुलिस व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिए है। दक बुधवार को शासन सचिवालय में सहकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों एवं सहकारी संस्थाओं में गबन, अनियमितताओं एवं अन्य प्रकरणों में दर्ज एफआईआर के संबंध में कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे।

दक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गबन, भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों में तुरंत अनुसंधान पूरा कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। गबन के प्रकरणों में दोषियों के विरूद्ध आपराधिक धाराओं में कार्रवाई के साथ ही वसूली भी सुनिश्चित की जाए।

फर्जीवाड़े और घोटालों के प्रकरणों में मुख्य आरोपियों के साथ ही पूरे नेटवर्क का खुलासा कर सभी के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। दोषियों द्वारा जिन परिजनों के नाम पर सम्पत्ति बनाई गई है, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई कर वसूली की जाए।सहकारिता मंत्री ने कहा कि गंभीर प्रकृति के प्रकरणों में जिस मंशा के साथ आरोपियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, उसी के अनुरूप कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे प्रकरणों में बिना पर्याप्त आधार के एफआर लग जाने से गलत संदेश जाता है। अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में समय पर चालान प्रस्तुत किये जाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर अलग सेल का गठन कर ऐसे प्रकरणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। दक ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सहित अन्य कार्यों में फर्जीवाडे एवं अनियमितताओं के कुछ बड़े प्रकरण सामने आए हैं, जिनसे विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसे प्रकरणों पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। उन्होंने फर्जीवाड़े में शामिल ई-मित्र संचालकों एवं बैंक खाते किराये पर देने वाले लोगों के विरूद्ध भी कार्रवाई के निर्देश दिए।रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने कहा कि गबन एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में विभाग द्वारा सहकारी अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। केवल गंभीर प्रकृति के मामलों में ही एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। चूंकि प्रकरण की पूर्व में जांच हो चुकी होती है तथा आरोपी भी ज्ञात होते हैं, अत: अधिकांश प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस के स्तर पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में सख्त कार्रवाई होने से निचले स्तर तक स्पष्ट संदेश जाएगा और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। पुलिस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि आगामी दिनों में कार्यवाही में गति लाते हुए लम्बित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण किया जाएगा। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक, गृह विभाग दीपक कुमार, डीआईजी, सीआईडी (सी.बी.) दीपक भार्गव, राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी, पुलिस अधीक्षक (एसीबी) गोरधन लाल, संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता प्रह्लाद सहाय नागा, एडिशनल डीसीपी जयपुर नीतिराज सिंह मौजूद थे।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बुधवार को विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों एवं सहकारी संस्थाओं में गबन-अनियमितताओं के प्रकरणों में दर्ज एफआईआर के संबंध में कार्यवाही की समीक्षा की।

- **सहकारिता मंत्री के गृह विभाग, पुलिस व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों को निर्देश दिए**

मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में केवल डिप्लोमा वाले ही पात्र

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती-2021 में नियुक्तियों का रास्ता साफ करते हुए एकलपीठ को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश मनोज शर्मा व अन्य की ओर से दायर अपीलों का निस्तारण करते हुए दिए। एकलपीठ ने 22 फरवरी, 2023 को याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड के 15 दिसंबर, 2021 के कार्यालय आदेश को रद्द कर भर्ती विज्ञापन के अनुसार इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों को हटाते हुए परिणाम जारी करने को कहा था। खंडपीठ ने लंबित भर्ती प्रक्रिया को तत्काल पूरी करने के आदेश देते हुए कहा है कि एकलपीठ के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। ऐसे में उसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा कि यह स्थापित नियम है कि एक बार खेल शुरू होने के बाद उसने नियमों को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में राज्य सरकार ने बाद में नियम संशोधित कर दिया तो भी वह संशोधन की तारीख से ही प्रभावी होगा और उसे पहले से जारी भर्ती विज्ञापन पर लागू नहीं किया जा सकता।

जैसलमेर : सैकड़ों मृत गौवंश के मामले में आयुक्त पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप

जैसलमेर में नगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड में सैकड़ों मृत गौवंश मिलने के मामने ने तूल पकड़ा

- करणी सेवा संस्थान से जुड़े हाकमदान का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से पहले कई बार नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढा को शिकायत दी गई थी
- 'मामले में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, मजबूर होकर उन्हें पूरा मामला सार्वजनिक करना पड़ा'
- मामले में साधु-संतों ने भी नाराजगी जताई है, मुस्लिम समाज ने ईद के मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने तथा हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की

जैसलमेर, (निसं)। जैसलमेर में नगर परिषद के कचरा डंपिंग यार्ड में सैकड़ों मृत गौवंश मिलने का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ चुका है। इस मामले को उजागर करने वाले करणी सेवा संस्थान से जुड़े हाकमदान का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से पहले कई बार नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढा को शिकायत दी गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूर होकर उन्हें पूरा मामला सार्वजनिक करना पड़ा।

डंपिंग यार्ड में मृत गायों के खुले में पड़े रहने, सड़ांध फैलने और कुत्तों द्वारा शवों को नोचे जाने के वीडियो सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि गौ संरक्षण के दावों की पोल खोलने वाला मामला है। करणी सेवा संस्थान के हाकमदान ने कहा कि हमने कई बार नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह को मौखिक और लिखित शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब स्थिति असहनीय हो गई तब वीडियो सोशल मीडिया पर डालना पड़ा। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो मामला इतना भयावह नहीं बनता।

मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। साधु-संतों ने भी नाराजगी जताई है, जबकि मुस्लिम समाज ने ईद के मौके पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजने तथा हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है। घटना सिर्फ एक डंपिंग यार्ड की नहीं, बल्कि पशु संरक्षण, नगर निकायों की जवाबदेही और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई होती तो यह मामला राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं बनता।

लालू सिंह सोढा, बजरंग दल नेता ने बताया कि गौवंश के शवों का खुले में पड़ा होना बेहद चिंताजनक है। इससे गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरधरसिंह सोढा ने बताया कि गुनाहगार खुद नगर परिषद जैसलमेर आयुक्त महोदय है कितना बड़ा कमीशन लेता है आप सोच भी नहीं सकते हैं और बलि का बकरा ठेकेदार को बनाया गया क्यों फिर नगर परिषद जैसलमेर के अधिकारी लोगों का कोई रोल नहीं है, फिर कमीशन खाते हैं तो अधिकारी लोगों को भी भुगतना चाहिए।

शहर के वरिष्ठ नागरिक चम्पालाल ने बताया कि आयुक्त लजपालसिंह भूखंड को घरेलू से व्यवसायिक करवाने के दलाल के जरिए 20 लाख रुपए लेकर फाइल स्वीकृत कर रहे हैं। भूखंड के पास स्टेप लेंड स्वीकृत हेतू 7 लाख ले रहे हैं। जनता भ्रष्ट आयुक्त से दुखी है, राज्य सरकार मौन है, उसी का नतीजा है गौधन कांड। भाजपा दिल्ली सरकार को आयुक्त लजपालसिंह के कार्यकाल के फैसलों की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाकर दूध का दूध पानी का पानी करवाना चाहिए अन्यथा भाजपा की साख को नुकसान पहुंचेगा।

नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढा ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए मृत पशुओं के निस्तारण का ठेका संभाल रहे ठेकेदार गोपाराम मेघवाल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। कारण बताओ नोटिस जारी कर ठेका निरस्त कर दिया और धरोहर राशि भी जब्त की गई। इसके बाद जेसीबी मशीनों से गड्ढे खुदवाकर मृत पशुओं को दफनाने का काम शुरू किया गया। जांच में कई शव एक से डेढ़ महीने पुराने पाए गए।

'भारत-पाक बॉर्डर के 15 किमी. दायरे में अवैध निर्माण जमींदोज होंगे'

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में सुरक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीकानेर में कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की सुरक्षा बैठक ली।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर/बीकानेर । केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बीकानेर में कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की सुरक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत-पाकिस्तान सीमा बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स को और मजबूत करें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे प्रत्येक जिले में 15 कि.मी. के दायरे में सभी अवैध निर्माण जमींदोज किए जाएं।

अमित शाह ने प्रदेश में घुसपैठ, नारकोटिक्स तस्करी, अतिक्रमण, आतंकवादी फंडिंग और अन्य सीमा-पार अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए कहा। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और राज्य सरकार को इसके लिए समन्वित सीमा प्रबंधन रणनीति अपनाने के लिए कहा। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी तथा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर व फलौदी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।

बैठक में प्रत्येक सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय हुआ। अमित शाह ने जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे सभी बैंकों में पूर्ण कानूनी एवं वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करें, प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सत्यापन करें, उनके फंडिंग स्रोतों की जांच करें, म्यूल खातों एवं शेल कंपनियों को ट्रैक करें, फर्जी आधार कार्डों की पहचान करें तथा तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करें। सीमावर्ती गांवों में सभी सरकारी योजनाओं का 100 प्रतिशत सैचुरेशन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

- अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ, नारकोटिक्स, अतिक्रमण, आतंकी वित्तपोषण और सीमा-पार अपराधों पर शिकंजा कसने की हिदायत दी

हाईकोर्ट ने आसाराम की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी

आसाराम को तत्काल सरेंडर करने के आदेश दिए

- राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने सेवादार शरतचंद्र और शिल्पी को पूरी तरह से आरोप मुक्त किया

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने अपने ही आश्रम की नाबालिग छात्रा से यौन उत्पीडन मामले में आसाराम को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। बुधवार को जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने आसाराम समेत तीन आरोपियों की अपीलों पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि निचली अदालत द्वारा दी गई सजा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि अदालत ने उन्हें गैंगरेप की धारा से बरी कर दिया, लेकिन अन्य गंभीर आरोपों में दोषसिद्धि कायम रखी गई है। साथ ही कोर्ट ने आसाराम बापू को तत्काल सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।

आसाराम की यौन शोषण मामले में प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अपील पर बुधवार को फैसला आया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपने फैसले में आसाराम को पूरी तरह से आरोप मुक्त नहीं किया है। उनकी सजा खत्म करने की अपील खारिज हुई है, लेकिन पॉक्सो एक्ट की गैर जमानती अपराध, आईपीसी की गैंगरेप और षड्यंत्र कर अपराध करने से जुड़ी धाराओं में दोषी नहीं माना है। खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की दुष्कर्म, पॉक्सो की यौन शोषण और जेजे एक्ट सहित अन्य धाराओं को लेकर लोअर कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सही ठहराया है, यानी सजा बरकरार रहेगी। खंडपीठ ने आसाराम बापू के सेवादार शरतचंद्र और शिल्पी को पूरी तरह से आरोप मुक्त कर दिया है।

इस मामले में पीड़िता के अधिवक्ता पीसी सोलंकी ने बताया कि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। आजीवन कारावास की सजा बरकरार है, राहत जरूर दी है। सोलंकी ने बताया कि बरी किए गए आरोपियों के आदेश के खिलाफ पीड़िता से बात कर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस फैसले के बाद आसाराम को अब जेल में सरेंडर करना होगा।

आसाराम फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत के तहत जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य कारणों से राहत दी थी, जिसकी अवधि कई बार बढ़ाई जा चुकी थी, लेकिन हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब उन्हें दोबारा सरेंडर करना होगा।

लूणकरणसर में दिन का तापमान 45 डिग्री पहुंचा

बाजारों में पसरा सन्नाटा, डॉक्टर्स ने धूप से बचने की सलाह दी

लूणकरणसर, (निसं)। प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बुधवार को लूणकरणसर का न्यूनतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा और अस्पतालों में डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई।

तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को जहां 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, वहीं बुधवार को इसमें एक डिग्री की और वृद्धि हुई। बुधवार को हवा की रफ्तार करीब 24 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, लेकिन गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को राहत देने के बजाय और अधिक परेशान किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर के समय सड़कों पर मिनी कर्फ्यू जैसा सन्नाटा दिखाई दिया। शहर के प्रमुख बाजारों और व्यस्त इलाकों में भीषण गर्मी का असर साफ तौर पर देखा गया। आम दिनों में लोगों और वाहनों से गुलजार रहने वाला हनुमान मंदिर रोड लगभग खाली नजर आया। रोझा चौराहा, चाटा बाजार, अनाज मंडी रोड, इंदिरा मार्केट और कालू रोड समेत अन्य बाजारों में भी भीड़ बेहद कम रही। तेज धूप और लू से बचने के लिए लोग पूरी तरह सतर्क दिखाई दिए। कई लोग चेहरे पर साफा बांधकर निकले, तो कुछ ने मास्क और सूती कपड़ों का सहारा लिया। दोपहिया वाहनों पर यात्रा करते समय लोग खुद को पूरी तरह कपड़ों से ढककर सफर करते दिखे। डॉक्टर्स ने लोगों को धूप में कम निकलने, अधिक पानी पीने और शरीर को हाइड्रेट रखने की सलाह दी है।

अजमेर में भीषण गर्मी में आग से ट्रांसफार्मर की केबल जली

- मदार नाड़ी क्षेत्र में सूखी झाड़ियों में अचानक आग लग गई थी

अजमेर, (निसं)। शहर में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी के बीच बुधवार को वार्ड संख्या 54 स्थित मदार नाड़ी क्षेत्र में सूखी झाड़ियों में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही स्थानीय निवर्तमान पार्षद सुनील धानका मौके पर पहुंचे और संबंधित विभागों को सूचित कर आग पर समय रहते काबू पाया गया। घटना में एक ट्रांसफार्मर की केबल तथा पानी की टंकी की समरसेबल लाइन जलने की जानकारी सामने आई है, हालांकि बड़ा नुकसान होने से बच गया।

सुनील धानका ने बताया कि क्षेत्र निवासी विशाल ने उन्हें फोन कर मदार नाड़ी क्षेत्र की सूखी झाड़ियों में आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे, जहां क्षेत्रवासी अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। आग तेजी से फैल रही थी और पास में विद्युत ट्रांसफार्मर होने के कारण खतरा बढ़ गया था। उन्होंने तुरंत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की मदार टीम तथा नगर निगम अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद दोनों विभागों की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से ट्रांसफार्मर की एक केबल जल गई, वहीं पास स्थित पानी की टंकी की समरसेबल लाइन को भी नुकसान पहुंचा। धानका ने बताया कि इन दिनों क्षेत्र में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और सूखी झाड़ियों में अत्यधिक तापमान के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि समय रहते आग पर नियंत्रण पा लेने से बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा आसपास के क्षेत्र में अधिक नुकसान हो सकता था।

अलवर के रैणी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई

- 6 जेसीबी, 5 पोकलेन और 25 ट्रैक्टर जब्त खनन विभाग और राजस्व विभाग की टीमों को भी मौके पर बुलाया

अलवर, (निसं)। अलवर जिले में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रैणी थाना इलाके में पुलिस की स्पेशल टीम ने करवाई करते हुए बजरी के अवैध खनन में लगी 6 जेसीबी, 5 पोकलेन मशीनें और 25 ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया।

बुधवार को पुलिस ने रैणी थाना इलाके में माफियाओं के ठिकानों पर अचानक दबिश दी। पुलिस की इस ताबड़तोड़ और अचानक हुई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया और कई लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर मौके से भाग खड़े हुए। एसपी सुधीर चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। इस टीम का नेतृत्व ट्रेनी आईपीएस कार्तिकेय वर्मा कर रहे थे। आईपीएस कार्तिकेय वर्मा के सुपरविजन में रैणी थानाधिकारी और उनकी पुलिस टीम ने पूरी योजना के साथ रैणी थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों और बजरी की अवैध खानों पर एक साथ छापेमारी की। पुलिस टीम को देखकर मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान अवैध बजरी खनन और ढोने में इस्तेमाल हो रही भारी मात्रा में मशीनों को अपने कब्जे में ले लिया। मौके से जेसीबी मशीनें, बड़ी पोकलेन मशीनें और कई ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया गया। जब्त की गई इन सभी गाड़ियों और मशीनों को पुलिस थाने लाया गया है, जहां इनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ गाड़ियों की जब्ती अलवर पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। कार्रवाई को पूरी तरह पुख्ता बनाने और मौके की सही पैमाइश के लिए पुलिस ने तुरंत ही खनन विभाग और राजस्व विभाग की टीमों को भी मौके पर बुला लिया। तीनों विभागों की टीमों ने मिलकर अवैध खनन क्षेत्र की जांच शुरू कर दी है।

बीकानेर : मूंगफली की प्रोसेसिंग यूनिटों पर कृषि विभाग की रेड

कई फर्मों में भारी अनियमितताएं मिलीं, टीमों ने मूंगफली बीज के नमूने लेकर विक्रय पर रोक लगाई

- लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बीकानेर की मूंगफली प्रोसेसिंग यूनिटें बिना वैध बीज लाइसेंस के ही मूंगफली दाने को बीज बताकर किसानों को बेच रही हैं

बीकानेर, (निसं)। कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर विभाग की 10 संयुक्त टीमों ने जिले की 10 मूंगफली फर्मों पर औचक छापेमारी की। लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बीकानेर की मूंगफली प्रोसेसिंग यूनिटें बिना वैध बीज लाइसेंस के ही मूंगफली दाने को बीज बताकर किसानों को बेच रही हैं। कार्रवाई के दौरान कई फर्मों में भारी अनियमितताएं मिलीं, जिसके बाद टीमों ने मूंगफली बीज के नमूने (सैंपल) आहरित कर उनके विक्रय पर तुरंत रोक लगा दी है।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) मदनलाल ने बताया कि नेशनल सीड्स, सुप्रीम, चारभुजा एग्रो इंडस्ट्रीज, जिंदल एग्रो इंडस्ट्रीज, बीकानेर फूड्स, जेडी इंडस्ट्रीज, आदर्श सीड्स, तिरुपति उद्योग, चारभुजा एग्रो शोभासर और वैभव लक्ष्मी फर्मों पर जांच कर 'सीड्स कंट्रोल ऑर्डर' व बीज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। टीम में उपनिदेशक जयदीप दोगने, सहायक निदेशक सुरेंद्र मारू, मुकेश गहलोत सहित सुभाष बिश्नोई, राजूराम डोगीवाल, रघुवर दयाल, मीनाक्षी शर्मा, रमेश भाम्भू, कविता गुप्ता, गिरिराज चारण, सोमेश तंवर, संगीता मेहता, महेंद्र विश्नोई, मेघराज बंजारा, मामराज मेघवाल, कन्हैयालाल शामिल रहे।

मंदिर जा रही महिला की बेरहमी से पीटकर हत्या

- युवक ने महिला को रास्ते से अपने घर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया
- पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार व उसकी मां को हिरासत में लिया

खेतड़ी, (निसं)। पचेरीकलां थाना क्षेत्र के रामसर में बुधवार को एक महिला की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला अपने घर से मंदिर जा रही थी कि गांव के एक युवक ने रास्ते से अपने घर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पर पचेरीकलां पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई।

जानकारी के अनुसार रामसर निवासी कमला देवी (60) पत्नी ख्यालीराम बुधवार को करीब दस बजे अपने घर से मंदिर जा रही थी। इस दौरान गांव का ही राजेश पुत्र महासिंह रास्ते से जा रही कमला देवी को जबरन पकड़ कर अपने घर ले गया। इस दौरान उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे महिला ने दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों ने बताया कि कमला देवी के सिर में धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई है। आरोपी राजेश का मकान मंदिर के पास ही है, जबकि कमला देवी का मकान घटनास्थल से करीब डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर है।

इस मामले में ग्रामीणों ने बताया कि राजेश कुमार सनकी है जिसने वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद भी आरोपी अपने घर पर ही रहा जो पुलिस आने के समय मौके पर मौजूद था। जिसके बाद पुलिस ने राजेश कुमार व उसकी मां नीता देवी को हिरासत में ले लिया। मृतक महिला कमला देवी का पति ख्यालीराम गांव में ही टैक्टर चलाकर मजदूरी करता है। इनके एक बेटा जितेंद्र दिव्यांग है तथा दूसरा बेटा सत्येंद्र है। घटना के समय मृतका का छोटा बेटा सत्येंद्र किसी काम से पचेरीकलां गया हुआ था। घटना की सूचना पर बुहाना डीएसपी नोपाराम भाकर, थानाधिकारी बनवारीलाल यादव भी मौके पर पहुंचे तथा घटनास्थल का मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई। डीएसपी नोपाराम भाकर ने बताया कि पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार व उसकी मां नीता देवी को हिरासत में लेकर पुछताछ की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बुहाना के राजकीय अस्पताल में भिजवाया है, मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है।

भरतपुर में 142 मॉडिफाइड साइलेंसरों को बुलडोजर से तोड़ा

- कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस ने लोगों से मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की

भरतपुर, (निसं)। शहर में तेज आवाज और पटाखे जैसी ध्वनि निकालने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए 142 साइलेंसरों को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस ने लोगों से ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल नहीं करने की अपील भी की।

यातायात पुलिस ने जब्त किए साइलेंसरों को बुलडोजर से नष्ट कराया।

ट्रैफिक इंचार्ज अजयसिंह ने बताया कि बुलेट बाइक में पटाखे जैसी आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया था। अभियान के दौरान ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई की गई, जो अपनी मोटरसाइकिलों में अवैध और मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर आमजन को परेशानी पहुंचा रहे थे। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत जब्त किए गए सभी साइलेंसरों को बुधवार को बुलडोजर के जरिए नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में कुल 142 साइलेंसरों का नष्टीकरण किया गया। अजय सिंह ने कहा कि यातायात पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे वाहनों में पटाखा साइलेंसर या अन्य अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं, ताकि लोगों को असुविधा और ध्वनि प्रदूषण से बचाया जा सके।

वांछित आरोपी गिरफ्तार

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी थाना पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने तथा सरकारी वाहन को टक्कर मारने के मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपी ईन्द्राज पुत्र श्रीराम को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार 9 सितंबर 2024 को सूचना मिली थी कि थाना उदयपुरवाटी क्षेत्र के ककराणा इलाके से एक युवक का अपहरण कर काले रंग की स्कॉर्पियो में कुछ लोग खेतड़ी की ओर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने अजीत अस्पताल के सामने नाकाबंदी शुरू की। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो तेज गति से मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने वाहन को रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका। नाकाबंदी तोड़ने के प्रयास में स्कॉर्पियो चालक ने डायल-112 वाहन को सामने से टक्कर मार दी।

आग से पांच ट्रॉली चारा जला

टोंक, (निसं)। सोप कस्बे की बैरवा ढाणी वार्ड नंबर 11 में बुधवार सुबह एक बाड़े में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से पशुओं के लिए रखा करीब पांच ट्रॉली सूखा चारा जलकर राख हो गया। साथ ही पास के बाड़े में रखी लकड़ियां और कंडे भी जल गए, इसके अलावा करीब आधा दर्जन पेड़-पौधे आग में जल गए। इससे पीड़ित मांगीलाल करसोलया पुत्र प्रभु करसोलया को करीब 40-45 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित मांगी लाल ने बताया कि शहीद बाबा के मकान के पीछे बने उसके बाड़े में बुधवार को अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई।

सिद्धमुख थाने के पुलिसकर्मियों पर महिला से बदतमीजी का आरोप

तारानगर, (निसं)।चूरू जिले के सिद्धमुख थाना अंतर्गत गांव दयावठ में पुलिसकर्मियों द्वारा घर में घुसकर महिला से बदतमीजी और अनुचित व्यवहार का मामला सामने आया है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने इस घटना को लेकर राजस्थान पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

विधायक बुड़ानिया द्वारा डीजीपी को दिए पत्र के अनुसार सिद्धमुख थाने के कुछ पुलिसकर्मी प्राइवेट बैंक के कार्मिकों के साथ गांव दयावठ निवासी किसान बलवान के घर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने घर की मुखिया महिला के साथ बदतमीजी व अनुचित व्यवहार किया एवं पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला को जबरन घसीटकर पुलिस वाहन में डालने का अमानवीय कृत्य किया, जो विधि के पूर्णत: विरुद्ध है। प्राइवेट बैंक के कार्मिकों ने पुलिस की आड़ लेकर किसान के पशुओं एवं छोटे-छोटे बछड़ों को 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में घर से बाहर निकाल दिया, जिससे पशुओं के जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया। विधायक नरेंद्र बुड़ानिया ने पत्र में लिखा है कि इस अत्यंत निंदनीय घटना से पूरे क्षेत्र में भारी आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है। आमजन में पुलिस की कार्यप्रणाली के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है। विधायक बुड़ानिया ने दोषी पुलिसकर्मियों तथा इसमें शामिल प्राइवेट बैंक के कार्मिकों के विरुद्ध तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को न्याय एवं सुरक्षा प्रदान की करने की मांग की है जिससे आमजन में पुलिस के प्रति सद्भाव एवं विश्वास बना रहे। विधायक ने डीजीपी से त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही कर न्याय दिलाने की अपील की है।

हम 12वें-13वें ओवर तक मुकाबले में थे, लेकिन हमारी फील्डिंग उस स्तर की नहीं थी। हमने कुछ कैच छोड़े और ग्राउंड फील्डिंग भी खराब रही। उन्होंने माना कि टीम दबाव के क्षणों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी।
- शुभमन गिल

पूर्व भारतीय खिलाड़ी, अपनी टीम को लेकर बोलते हुए।

आज का खिलाड़ी — विराट कोहली

विराट कोहली ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले क्वालीफायर मैच में इतिहास रच दिया है। 43 रन बनाते ही विराट ऐसे पहले बल्लेबाज बन गए, जिन्होंने लगातार चार सीजन में 600 रन बनाए हों। विराट इससे पहले 2023, 2024 और 2025 में भी 600 से अधिक रन बना चुके हैं। विराट ने अब आईपीएल 2026 सीजन में 15 मैच खेलकर 600 रन बना लिए हैं। गुजरात के खिलाफ क्वालीफायर 1 में उन्होंने 25 गेंद में 43 रनों की पारी खेली।

क्या आप जानते हैं ?... वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा ने 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 400 रन बनाए थे, जो आज भी अटूट है।

हैदराबाद आईपीएल से बाहर, राजस्थान ने 47 रन से हराया

सूर्यवंशी ने 29 बॉल पर 97 रन बनाये, आर्चर को 3 विकेट

चंडीगढ़, 27 मई। सनराइजर्स हैदराबाद 2026 से बाहर हो गई है। टीम को एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने 47 रन से हरा दिया। क्वालीफायर-2 में 29 मई को राजस्थान का मुकाबला न्यू चंडीगढ्ढ में गुजरात टाइटंस से होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम 31 मई को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल खेलेगी। बुधवार को मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद 19.2 ओवर में 196 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।

राजस्थान को वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 7.6 ओवर में 125 रन जोड़ दिए। सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 12 छक्के शामिल रहे। वहीं जायसवाल ने 29 रन बनाए। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने 21 गेंदों में 50 रन ठोके, जबकि कप्तान रियान पराग ने 12 गेंदों में 26 रन की पारी खेली। अंत में रवींद्र जडेजा 12 रन बनाकर नाबाद लौटे। हैदराबाद की ओर से प्रफुल हिंगे सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट लिए। ईशान मलिंगा, शिवांग कुमार और नीतीश रेड्डी को 1-1 विकेट मिला। हालांकि कप्तान पैट कमिंस काफी महंगे साबित हुए और 4 ओवर में 64 रन खर्च कर बैठे।

वैभव बने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, क्रिस गेल का रिकार्ड किया ध्वस्त

नई दिल्ली, 27 मई। वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला बुधवार शाम को भी जारी रहा। न्यू चंडीगढ़ में 2026के एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के युवा बल्लेबाज ने गदर काट दयिा। पारी के पहले चार ओवरों में ही सात छक्के जड़कर उन्होंने एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए 59 छक्के लगाए थे। सूर्यवंशी ने 2026 में हैदराबाद के गेंदबाज साकिब हुसैन के चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना 60वां छक्का लगाकर उस आंकड़े को पार कर लिया।

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दयिा है। गेल ने आईपीएल 2012 में 59 छक्के लगाए थे। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खलिाफ बुधवार को आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर में गेल का रिकॉर्ड तोड़ा।

सूर्यवंशी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड

सूर्यवंशी के नाम अब दुनिया भर में खेले जाने वाले किसी भी 20 टूर्नामेंट के एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। साकिब हुसैन के ओवर में छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने के तुरंत बाद सूर्यवंशी ने डीप मिड-विकेट के ऊपर से एक और शॉट लगाया और 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।

कॉल्विन शील्ड टूर्नामेंट के पहले रोमांचक मुकाबले में दौसा ने बारां को हराया

दौसा, 27 मई। जिला क्रिकेट संघ दौसा के सचिव श्री बृज किशोर उपाध्याय ने बताया कि आज दिनांक 27 मई 2026 को आरसीए द्वारा आयोजित कॉल्विन शील्ड टूर्नामेंट में दौसा का पहला मुक़ाबला बारां से हुआ उसमें दौसा ने 18 रन से जीत दर्ज की है बारां ने टॉस जीतकर फील्डिंग को चुना ।दौसा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने निर्धारित 49.3 ओवर में 242/10 रन बनाए जवाब में बारां की टीम 224 रन 10 विकेट पर सिमट गई ।दोसा की ओर से सचिन शर्मा कप्तान ने ताबड़तोड़ 19 बॉल पर 57 रन बनाए और दो विकेट भी लिए कप्तान ने ऑलराउंड प्रदर्शन

किया उसके अलावा दौसा की टीम में प्रोफेशनल खिलाड़ी दिव्यांश शर्मा ने घातक गेंदबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 25 रन देकर चार महत्वपूर्ण विकेट और 16 रन बनाए ।इसके अलावा करण मीणा ने दो और अनुज मीणा ने एक विकेट लिए साथ ही दिव्यांशु घोषिंगा ने 40 रन,देवकृत शर्मा ने 34 रन ,एवं लीलाधर मीणा ने 33 रन बनाए । जिला क्रिकेट संघ के सचिव श्री बृजकिशोर उपाध्याय ने ग्राउंड और होटल में मिलकर खिलाड़ियों। का हौसला अफजाई किया साथ ही उन्होंने कहा कि अभी दौसा की टीम में और सुधार करने की आवश्यकता है जो समय रहते किया जाएगा ।डीसीए के पदाधिकारियों ने टीम के सभी खिलाड़ियों को और कोच और मैनेजर प्रेम सिंहऔर सुखराम गुर्जर को शुभकामनाएं दी और आगे के मैच में खिलाड़ियों को जीत के लिए मोटिवेट किया ।दौसा का दूसरा मुकाबला सवाई माधोपुर से 28.05.26 को होगा।इसके लिए टीम में कुछ बदलाव करना पड़ेगा जो खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए है उनको बाहर कर दूसरे खिलाड़ियों को मौका देंगे।

हार्दिक का इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट

नई दिल्ली, 27 मई। भारत के ऑलराउंडर और मुंबई इंडियंस के कप्तानहार्दिक पंड्याने बुधवार को अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया। इस प्लेटफॉर्म पर उनका अकाउंट सर्च करने पर (यूज़र नहीं मिला) लिखा हुआ आने लगा। उनके यूजरनेम से सर्च करने पर भी उनका प्रोफाल शो नहीं हो रहा। यह सब तब हुआ, जब पांच बार की चैंपियन टीम पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही। 2026सीजन के दौरान हार्दिक पंड्या काफी चर्चा में रहे थे। उनका नाम कई दूसरी फ्रेंचाइजियों से भी जोड़ा गया। सोशल मीडिया पर तो यह भी कहा जाने लगा कि जल्द ही कोई ट्रेड (खिलाड़ियों की अदला-बदली) हो सकती है। इतना ही नहीं, सूर्यकुमार यादव, मुंबई इंडियंस को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किए जाने की भी चर्चा थी। हाल में पंड्या ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की, जिससे इंटरनेट पर हलचल मच गई।

प्रथम राजस्थान सीनियर विमेंस फुटबॉल लीग

पांचवें दिन जयपुर सिटी ने रॉयल फुटबॉल क्लब को जयपुर को 6-0 से हराया

जयपुर, 27 मई। राजस्थान फुटबॉल संघ के तत्वावधान में जयपुर स्थित राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ग्राउंड पर आयोजित प्रथम राजस्थान सीनियर विमेंस फुटबॉल लीग के पांचवें दिन दो मुकाबले खेले गए। संघ सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पहला मुकाबला सुबह 7:00 बजे जयपुर सिटी एफसी एवं रॉयल एफसी जयपुर के मध्य खेला गया। दोनों ही टीमों ने शुरुआत से आक्रामक खेल दिखाया तथा एक-दूसरे के गोल पर लगातार दबाव बनाया। जयपुर सिटी एफसी को मैच के तीसरे मिनट में 22 नंबर खिलाड़ी संध्या, के शानदार गोल से 1-0 की बढ़त मिली। इसके बाद दुसरा गोल 15 मिनट में भानुप्रिया, ने किया तीसरा गोल 45 वे मिनट में तारा, ने किया। चौथा और पांचवा गोल 61 और 88 मिनट में निशा, ने किया। और अंत में छटा गोल 90 2 मिनट में दीक्षा कुमारी, ने किया । इस प्रकार 6-0 से एकतरफा इस मुकाबले को अपने नाम किया। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब निशा को दिया गया। दूसरा मुकाबला शाम 4:00 बजे जिंक फुटबॉल अकैडमी एवं रियल जयपुर फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। इस मुकाबले में जिंक फुटबॉल अकैडमी ने 3-2 से शानदार जीत दर्ज की। रियल एफसी की ओर से नेहा ने (7वां मिनट), रजनी शर्मा ने (44 मिनट) में गोल

किए। और जिंक फुटबॉलर अकादमी की ओर से मोना ने 13 मिनट में पहला गोल किया और अंतारा ने 55 मिनट में जिंक फुटबॉल अकादमी के लिए दूसरा गोल किया। और अंत में तीसरा और निर्णायक गोल जिंक फुटबॉल अकादमी की 10 नंबर जर्सी में खेल रही खिलाड़ी प्रियंका ने किया। और इस तरह से जिंक फुटबॉल अकादमी ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबला तीन दो से अपने नाम किया। मुकाबलों में अमर सिंह ने मैच कमिश्नर की भूमिका निभाई, जबकि अवकाश दायमा, संजय लंबा,अंकित शर्मा और मोहम्मद मुस्तफा ने निर्णायक की जिम्मेदारी संभाली।

जयपुर की दिव्यांशी ने एशियन चैम्पियनशिप में जीता कांस्य

जयपुर, 27 मई। गुलाबी नगर की स्क्वैश खिलाड़ी दिव्यांशी जैन ने चीन में संपन्न 33वीं लिनिंग एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, जबकि जयपुर के ही एक अन्य खिलाड़ी धैर्य गोगिया क्वार्टर फाइनल में हारकर 5वें स्थान पर रहे। भारतीय दल की कोच जयपुर की सुरभि मिश्रा ने बताया कि टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने पूर्व की अपेक्षा इस बार अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य समेत कुल आठ पदक जीते। भारत ने कोरिया में हुई पिछली एशियन चैंपियनशिप में सात पदक जीते थे। दिव्यांशी को गर्ल्स अंडर-13 के सेमी फाइनल में जापान की

रियो योशिनो से 8-11, 11-7, 6-11, 11-4, 12-10 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरे सेमी फाइनल में भी भारतीय खिलाड़ी शनाया परसरामपुरिया को सिंगापुर की करीना शशि कुमार ने 11-5, 11-6, 13-11 से शिकस्त दी। दिव्यांशी और शनाया को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सुरभि ने बताया कि जयपुर के धैर्य गोगिया ने पहले राउण्ड में ही 5वीं वरीयता के हांगकांग के टेसेका चुन को 12-10, 10-12, 11-7, 11-7 से हरा बड़ा उलटफेर किया लेकिन उनका सफर क्वार्टर फाइनल में थम गया। जहां भारत के ही अमार्य बजाज ने धैर्य को 11-9, 11-9, 11-4 से हराया। धैर्य 5वें स्थान पर रहे। सुरभि ने बताया कि भारत के लिए बॉयज अंडर-19 कैटेगरी में आर्यवीर दीवान ने स्वर्ण पदक जीता। अमार्य बजाज ने बॉयज अंडर-13 कैटेगरी में, अनिका दुबे ने गर्ल्स अंडर-17 में और शिवेन अग्रवाल ने बॉयज अंडर-17 कैटेगरी में रजत पदक हासिल किए। वहीं बॉयज अंडर-17 में लोकेश और बॉयज अंडर-13 में अभ्युदय अरोड़ा ने भी कांस्य पदक अपने नाम किए।

कार्यालय नगर पालिका बौली, जिला-सवाई माधोपुर

क्रमांक :- न.पा.बौ./नि.शाखा/2026-27/354 दिनांक :- 22/05/2026

ई-निविदा सूचना वर्ष 2026-27

केन्द्र एवं राज्य सरकार में उपयुक्त श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर पालिका/परिषद/निगम/स्वायत्त शासन विभाग के निविदाताओं से आयुक्त/अधिशाषी अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित निविदा आमंत्रित की जाती है कार्य की अनुमानित लागत 40.00 लाख है। टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण राजस्थान सरकार के पोर्टल Website www.sppp.raj.nic.in, www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। NIB Code- DLB2627A2162

स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट का UBN Code- DLB2627WSOB05553

राज.संवाद/सी/26/3628 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बौंली

कार्यालय नगर पालिका, सीकरी जिला - डीग (राज.)

क्रमांक :- न.पा.सीकरी/2026/425 दिनांक :- 21/05/2026

ई-निविदा सूचना - 01/2026-27

नगरपालिका सीकरी के द्वारा निम्न कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्यता प्राप्त उचित श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई-निविदा द्वारा कुल 01 कार्य की कुल अनुमानित लागत 36.94 लाख रूपये की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। आंशिक अथवा पूर्णतः ई-निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निविदा स्वीकृत अधिकारी होगा। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी व शर्ते कार्यालय एवं विभाग की बेबसाईट http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in देखी/पढी जा सकती है। जिसके UBN NO. निम्नलिखित है। Nib Code – DLB2627A2085, UBN No. – DLB2627SLOB05404, Pub.Date – 21.05.2026

राज.संवाद/सी/26/3633 अधिशाषी अधिकारी

COLLEGE OF AGRICULTURE
(S.K.N. Agriculture University) Kumher, Distt. - Deeg, PIN- 321201

No. :- F./E Tender/COA-K/2026/6991 Date :- 21/05/2026

NOTICE INVITING E-BID

Bids are invited up to 05.00 P.M. of 01.06.2026 for LABOUR FOR AGRICULTURE AND OTHER OFFICIAL WORK at College of Agriculture, Kumher (Deeg). The details are available in the Bidding Documents which can be availed from the office of The Dean, College of Agriculture, Kumher (Deeg) 321201 or can be accessed or downloaded from State Procurement Portal website sppp.raj.nic.in or https://eproc.rajasthan.gov.in or university website www.sknau.ac.in. The bidding document after filling up properly can be uploaded on website https://eproc.rajasthan.gov.in along with payment of Rs. 1000/- through banker's cheque/demand draft in favour of Dean, College of Agriculture, Bharatpur. UBN No. : SKN2627SLOB00053

Raj.Samwad/C/26/3548 DEAN

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक :- जोविप्रा/2026-27/405 दिनांक :- 25/05/2026

ई-निविदा सूचना संख्या - मुख्यालय/09/2026-27

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था जो निविदा की निर्धारित शर्तो को पूर्ण करती है, से निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। इन कार्य की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्ते आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट www.jodhpurjda.org, www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है।

UBN No. : JOD2627GLOB00089, JOD2627GLOB00090

राज.संवाद/सी/26/3543 अधिशाषी अभियंता

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम), कॉरपोरेट कार्यालय, 04, मीरा मार्ग, उदयपुर- 313001(राज.)
फोन नम्बर: (0294)2428768/2428763-67, फैक्स: (0294)2428768, 2428739

ई-निविदा सूचना दिनांक :- 19/05/2026

ई-निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
ई-निविदा संख्या 03/2026-27 UBN No. MML2627GLOB00041	आरएसएमएमएल, कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग, उदयपुर पर पूरी तरह से स्वचालित यात्री लिफ्ट की आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग हेतु। अनुमानित मात्रा – 01, धरोहर राशि (रु. में) 30,000/-, निविदा प्रपत्र मूल्य (रु. में) 1180/-

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmm.com / www.sppp.rajasthan.gov.in अथवा प्रबंधक (एमएम) से उपरोक्त पतें पर सम्पर्क करें।

राज.संवाद/सी/26/3257 उप महाप्रबन्धक (का.एवं प्रशा.)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि., जिला खण्ड,अजमेर

क्रमांक 524 दिनांक- 21.05.2026

संशोधन निविदा सूचना संख्या 06/2026-2027

इस कार्यालय की ई-निविदा, सूचना संख्या 06 वर्ष 2026-27 में वर्णित कार्यों की निविदा राशि एवं निविदा शुल्क मे आंशिक संशोधन किया गया है जिसका विवरण वेब साईट www.dipronline.org, http://eproc.rajasthan.gov.in, https://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

DIPR/C/9315/2026 अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड रतनगढ़

क्रमांक: - 362-371 **ई-निविदा सूचना संख्या: 03/2026-27** दिनांक::- 20-05-2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला चूरू में सड़क निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों तथा केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के "एए" श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण बेवसाईट साईट www.dipronline.org व www.eproc.rajasthan.gov.in एव www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB No.: PWD2627A0675
UBN No : 1. PWD 2627WSOB03014, 2. PWD 2627WSOB03015, 3. PWD 2627WSOB03016, 4. PWD 2627WSOB03017

DIPR/C/9222/2026 अधिशाषी अभियन्ता सानिवि. खण्ड रतनगढ़

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: सं. वि.सं. 03/EXAM/APO/EP-I/2026-27 दिनांक : 27.05.2026

आयोग द्वारा गृह विभाग (अभियोजन) के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी (Assistant Prosecution Officer) के कुल 371 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।
आवेदन अवधि	दिनांक 08.06.2026 से दिनांक 07.07.2026 रात्रि 12-00 बजे तक।
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

अन्य बिन्दु व सूचना :- एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन / सूचना/ स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

DIPR/C/-------/2026 (रामनिवास मेहता) सचिव

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक: सं.वि.सं. 02/ परीक्षा/RAS&RTS/RPSC/EP-I/2026-27 दिनांक : 27.05.2026

आयोग द्वारा कार्मिक (क-4/2) विभाग के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2026 के कुल 607 (राज्य सेवाएं-192 एवं अधीनस्थ सेवाएं-415) पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता, सेवावार पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।
आवेदन अवधि	दिनांक 04.06.2026 से दिनांक 03.07.2026 रात्रि 12-00 बजे तक।
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

अन्य बिन्दु व सूचना : एकबारीय पंजीयन शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश तथा सम्बन्धित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त इस परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन / सूचना / स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.- 0145-2635212 एवं 2635200 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

DIPR/C/-------/2026 (रामनिवास मेहता), सचिव

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

क्रमांक :- लेखा/भ.वि.प्रा./2026-27/6095 - 6106 दिनांक :- 20/05/2026

ऑनलाईन निविदा सूचना सं. 13/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भरतपुर विकास प्राधिकरण, में उपयुक्त श्रेणी एवं विभिन्न विभागों में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से कुल 05 कार्यो हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जातीहै।

उक्त कार्यो का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत राषि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in, https://bda.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in portal पर देखा जा सकता है।

निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.inportal का अवलोकन करें।

UBN विवरण :- WAQ2627WSOB00041, WAQ2627WSOB00042, WAQ2627WSOB00043, WAQ2627WSOB00044, WAQ2627WSOB00045

राज.संवाद/सी/26/3544 अधिशाषी अभियन्ता

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड टोडाभीम

क्रमांक : 587-595 **ई-निविदा सूचना संख्या: 05/2026-27** दिनांक: 20.05.2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला करौली (खण्ड टोडाभीम) में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के तहत सामग्री आपूर्ति कार्य करवाने के लिये उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार /केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के विभिन्न सक्षम श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा से संबंधित समस्त विवरण बेवसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से बेवसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना आवश्यक है।

NIB Code PWD2627A0682
1 UBN No. PWD2627WSRC03027
DIPR/C/9134/2026

(के०के० मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड टोडाभीम

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, PWD, DISTRICT DIVISION, PHULERA

No. :- 337 **Notice Inviting Bid** Date: 19.05.2026

Bids for Short Term NIT No. 01/2026-27 of Various 24 Nos. Works are invited from intersted bidders upto 22.05.2026 to 01.06.2026. Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.raj.nic.in) of the state and departmenal website. The approximate value of the procurement is Rs. 729.17 Lacs.

1. UBN No. PWD2627WSOB03174, 2. UBN No. PWD2627WSOB03175, 3. UBN No. PWD2627WSOB03177, 4. UBN No. PWD2627WSOB03178, 5. UBN No. PWD2627WSOB03179, 6. UBN No. PWD2627WSOB03178, 7. UBN No. PWD2627WSOB03185, 8. UBN No. PWD2627WSOB03187, 9. UBN No. PWD2627WSOB03181, 10. UBN No. PWD2627WSOB03232, 11. UBN No. PWD2627WSOB03234, 12. UBN No. PWD2627WSOB03236, 13. UBN No. PWD2627SSOB03238, 14. UBN No. PWD2627SSOB03240, 15. UBN No. PWD2627WSOB03241, 16. UBN No. PWD2627WSOB03242, 17. UBN No. PWD2627WSOB03243, 18. UBN No. PWD2627WSOB03244, 19. UBN No. PWD2627WSOB03245, 20. UBN No. PWD2627WSOB03246, 21. UBN No. PWD2627WSOB03247, 22. UBN No. PWD2627WSOB03248, 23. UBN No. PWD2627WSOB03249, 24. UBN No. PWD2627WSOB03250

DIPR/C/9306/2026 (Jitendra Kumar Meena) Executive Engineer, PWD Distt. Dn. Phulera

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० खण्ड- चौमहला

क्रमांक : 94 **निविदा सूचना संख्या 02/2026-27** दिनांक: 22.05.2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सडक/ भवन कार्यो के लिये उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकारके एए, ए, बी, सी, श्रेणीके संवेदकों के समकक्ष हो, से कार्यों हेतु ई- टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी।

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट http://dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp व http://www.pwd.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

(PWD2627WSOB03255)
(PWD2627WSOB03256)
(PWD2627WSOB03257)

DIPR/C/9296/2026 अधिशाषी अभियन्ता सा नि वि खण्ड चौमहला

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड चूरू

क्रमांक :- 528-547 **ई-निविदा सूचना संख्या: 04/2026-27** दिनांक: 21/05/2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से तहसील व जिला चूरु में निर्माण कार्यो के लिए उपयुक्त श्रेणी के सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई- टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। आर.पी डब्लयू.ए 100 की शर्त लागू होगी। निविदा से संबंधित विवरण बेबसाईट http://dipr.rajasthan.gov.in/tendrs.asp एंव विभागीय वेबसाईटhttp://eproc.rajasthan.gov.in व http://www.pwd.rajajasthan.gov.in तथा http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

NIB No. - PWD2627A0687

S.No.	UBN No.	S.No.	UBN No.
1	PWD2627WSOB03036	2	PWD2627WSOB03037
3	PWD2627WSOB03038		

DIPR/C/9236/2026 अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड चूरू

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि खण्ड राजगढ (चूरू)

क्रमांक: 253-63 **ई-निविदा सूचना संख्या: 04/2026-27** दिनांक: 19.05.2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से तहसील राजगढ जिला चूरु में निर्माण कार्यो के लिए उपयुक्त श्रेणी के सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम् दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। आर.पी डब्लयू.ए 100 की शर्त लागू होगी। निविदा से संबंधित विवरण बेबसाईट http://dipr.rajasthan.gov.in/tendrs.asp एंव विभागीय वेबसाईटhttp://eproc.rajasthan.gov.inhttp://www.pwd.rajajasthan.gov.in तथा http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

NIB No. PWD2627A0713

S.No.	UBN No.	S.No.	UBN No.
1	PWD2627WSRC03141	2	PWD2627WSRC03142
3	PWD2627WSRC03143		

DIPR/C/9208/2026 अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि खण्ड राजगढ (चूरू)

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड भीनमाल

क्रमांक: अअ/भीन/2026-27/307 दिनांक: 21.05.2026

निविदा सूचना संख्या: 04 वर्ष 2026-2027
NIB No. PWD2627A0690

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सडक कार्य के आधार पर उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवम् दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में कार्य जिनकी लागत राशि रू. 158.10 लाख है के लिए ईटेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है।

ऑनलाईन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख	: 26 मई 2026, 9:30 बजे से 05 जून 2026, सायं 06:00 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट http://dipr.rajasthan.gov.in व http://sppp.rajasthan.gov.in व http:// eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया http://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन सम्पादित की जायेगी। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट पर http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है। कार्यवार यू. बी.एन संख्या निम्नानुसार है।

UBN No. PWD2627WSOB03049
DIPR/C/9178/2026 अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड भीनमाल

प्रदेशवासी भीषण गर्मी व नौतपा के प्रभाव से बचें- भजनलाल

उन्होंने आमजन से पशु-पक्षियों के लिए दाना-पानी उपलब्ध कराने में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की

जयपुर, 27 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में भीषण गर्मी और नौतपा के मद्देनजर प्रदेशवासियों से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने एवं लू के प्रभावों से बचने के लिए जरूरी उपायों को दिनचर्या में अपनाने की अपील की है।

मुख्यमंत्री ने अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बच्चों-बुजुर्गों और अस्वस्थ व्यक्तियों की देखभाल करने के साथ ही प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

उन्होंने आमजन से आव्हान किया है कि गर्मी के इस दौर में संवेदनशीलता और करूणा की भावना से जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर छांव एवं शीतल जल की व्यवस्था करने तथा पशु-पक्षियों के लिए भी दाना-पानी उपलब्ध कराने में सक्रिय सहभागिता निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तेज गर्मी के इस दौर में हमारे जनगणना कर्मी मेहनत और समर्पण से अपना दायित्व निभा रहे हैं। इसलिए उनके घर आने पर सहयोग की भावना को प्राथमिकता देते हुए उनका आदर-सत्कार करें। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि तेज गर्मी के दौर में जनगणनाकर्मी मेहनत और समर्पण से अपना दायित्व निभा रहे हैं। उन्हें सहयोग दें व प्राथमिकता दें।**

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिलान करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के आदेश तक भी दे डाले।

इस मामले में राजश्री पान मसाला की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, परंतु उस पर सुनवाई बुधवार को नहीं हुई। सलमान खान की ओर से अदालत में बताया गया कि, वह राजश्री के "ब्रॉंड एम्बेसडर" है और उन्हें उपभोक्ता आयोग में इस मामले में पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वह केवल राजश्री ब्रांड की इलायची का विज्ञापन करते हैं, अन्य उत्पादों का नहीं। जिला उपभोक्ता आयोग में दर्ज शिकायत पान मसाले को लेकर है।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में जिला उपभोक्ता मंच के आदेश को राज्य उपभोक्ता आयोग में भी चुनौती दी गई थी, परंतु वहां से राजश्री व सलमान खान को राहत नहीं मिली थी। हालांकि 7 अप्रैल को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फिल्म अभिनेता सलमान खान व अन्य के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से जारी जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी। साथ ही अदालत ने विज्ञापन करने पर लगाई गई रोक के आदेश को भी रद्द कर दिया था।

असम विधानसभा ने बुधवार को यूसीसी विधेयक पारित किया

विधानसभा में विधेयक पर बहस के दौरान राज्य सरकार व विपक्ष में तीखी नोंकझोंक हुई

गुवाहाटी, 27 मई। असम विधानसभा में बुधवार को लंबी और तीखी बहस के बाद समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कर दिया गया। इसके साथ ही असम यूसीसी पास करने वाला देश का तीसरा तथा पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया।

विधानसभा में विधेयक को सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन मिला, जबकि विपक्षी दलों ने इसके कई प्रावधानों पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि यह कानून सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है। विधानसभा में बहस के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोंक-झोंक भी देखने को मिली। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह कानून व्यक्तिगत धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन विरोध के बावजूद विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।

- **विधेयक में कहा गया है कि यह कानून असम में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर लागू नहीं होगा।**

समान नागरिक संहिता (यूसीसी), असम, 2026 बिल पर पूरे दिन चली चर्चा के बाद, स्पीकर रंजीत कुमार दास ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से इसे पास कराने के लिए पेश करने को कहा।

विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें बिल को और ज़्यादा चर्चा के लिए एक सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कही गई थी।

इस बिल में यह भी कहा गया है कि यह कानून असम में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। इस बिल में कई दंडात्मक उपायों का प्रस्ताव किया गया है, जिनमें दो शादियां या बहुविवाह करने पर सात साल की जेल और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन न कराने पर तीन महीने की जेल की सजा शामिल है।

इस बिल के तहत, शादी के 60 दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा, जबकि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। नियमों का पालन न करने पर सज़ा का भी प्रावधान है। तय समय सीमा के भीतर जान-बूझकर शादी या तलाक का रजिस्ट्रेशन न करवाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

वेणुगोपाल ने कर्नाटक पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेताओं के मुताबिक, सौहार्दपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की उम्मीद में कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को राज्यसभा सीट, दिल्ली में पार्टी मामलों में अधिक भूमिका और डीके शिवकुमार सरकार में उनके समर्थकों को उचित हिस्सेदारी देने की पेशकश की है। सिद्धारमैया ने यह प्रस्ताव सुनने के बाद, इस पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा है।

अब सवाल यह है कि डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कब लेंगे?

सूत्रों ने दो संभावनाएं बताई हैं। पहली, सिद्धारमैया गुरुवार या शुक्रवार तक इस्तीफा दे सकते हैं और नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह इसी सप्ताहांत में हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, यह संभावना ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन की योजना पर सहमति बन चुकी है और पार्टी को उम्मीद है कि सिद्धारमैया जल्द ही पद छोड़ देंगे।

लेकिन राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, जब तक वह वास्तव में हो न जाए। यदि सिद्धारमैया अपना पद छोड़ने में देरी करते हैं, तो सूत्रों का कहना है कि शपथ ग्रहण समारोह राज्यसभा चुनावों, यानी 18 जून, के बाद तक टल सकता है।

सूत्रों के अनुसार, राज्य में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं और कांग्रेस ने उनमें से एक सीट सिद्धारमैया को देने का प्रस्ताव रखा है। दूसरी सीट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल सकती है, जो राज्य से वर्तमान सांसद हैं, जबकि तीसरी सीट डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश को दिए जाने की संभावना है। इसलिए, यदि अगले कुछ दिनों में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तो कांग्रेस इसे राज्यसभा चुनाव के बाद करना पसंद करेगी, क्योंकि नेतृत्व उच्च सदन के इस महत्वपूर्ण चुनाव से पहले किसी भी आंतरिक राजनीतिक खींचतान से बचना चाहता है। जहां डीके शिवकुमार खेमे में खुशी का माहौल है, वहीं सिद्धारमैया अभी भी अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोल रहे हैं। बुधवार को बेंगलुरु पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने दिल्ली बैठकों और संभावित नेतृत्व परिवर्तन पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पत्रकारों के सवालों पर उनका सिर्फ इतना जवाब था, "मैं कल बोलूंगा।"

सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया खेमे की कोशिश है कि डीके शिवकुमार सरकार में कई उपमुख्यमंत्री बनाए जाएं, ताकि शक्ति संतुलन बना रहे। वे यह भी चाहते हैं कि किसी सिद्धारमैया समर्थक को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए। यह पद फिलहाल डीके शिवकुमार के पास है।

डीके शिवकुमार खेमे के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि जल्द ही मुख्यमंत्री बनने वाले शिवकुमार एक उपमुख्यमंत्री के लिए सहमत हो सकते हैं, लेकिन कई उपमुख्यमंत्रियों के लिए नहीं। शिवकुमार के लंबे समय से प्रतीक्षित राजतिलक से पहले, पर्दे के पीछे बातचीत और राजनीतिक सौदेबाजी का दौर जारी है।

डीके शिवकुमार गुरुवार सुबह सिद्धारमैया से नाश्ते पर मिलने वाले हैं। देखना यह है कि इडली, सांभर और वड़ा के साथ क्या मुख्यमंत्री शिवकुमार को कोई "मीठी सौगात" देंगे या फिर देरी का एक और तड़का लगाएंगे?

महेश जोशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को उसके पिता महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान उसके परिजनों को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से नहीं बताए गए। जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रावधान है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को गिरफ्तार करने के कारणों की जानकारी लिखित रूप में उसके परिजनों को दी जाएगी। याचिका में कहा गया कि एसीबी की ओर से लिखित में परिजनों को यह जानकारी नहीं देने से यह गिरफ्तारी ही अवैध हो गई है। और उन्हें दिया गया पुलिस रिमांड और उसके बाद की कार्रवाई दूषित हो गई हैं। ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले को लेकर न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी शुभांशु दीक्षित, निरील कुमार, सुशील कुमार दिनेश गोयल और अरुण श्रीवास्तव की जमानत याचिकाओं पर बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। और एसीबी कोर्ट में भी पूर्व आईएएस सुबोध अग्रवाल की जमानत अर्जी पर बहस पूरी हो गई है।

पाक की दुविधा, ट्रंप की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन बाद में उसी पोस्ट में उन्होंने "सऊदी अरब और कतर द्वारा तत्काल हस्ताक्षर" किये जाने की मांग की। इसका मतलब है कि छूट वास्तव में केवल पाकिस्तान के लिए है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्योंकि ट्रंप ने आगे यह भी कहा कि यदि कोई देश हस्ताक्षर नहीं करता, तो "उसे इस समझौते का हिस्सा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह उसकी गलत मंशा दिखाता है।" हालांकि पाकिस्तान ने बाहरी तौर पर मजबूत रुख दिखाते हुए कहा है कि उसे इससे बाहर रहने का विकल्प दिया गया है, लेकिन वह खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि इसका मतलब यह है कि वह फिर भी "समझौते का हिस्सा" बना रहेगा या नहीं। अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर न करने से ट्रंप की नाराजगी मोल लेने की संभावना के अलावा पाकिस्तान के सामने एक और दुविधा है। पाकिस्तान लंबे समय से संघर्षरत पक्षों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय रहा है और उसे उम्मीद थी कि संघर्ष का समाधान होने पर पश्चिम एशिया में उसे सुरक्षा, कूटनीतिक और आर्थिक अवसर मिलेंगे।

पाकिस्तान पहले से ही यह सपना देख रहा है कि वह क्षेत्रीय केन्द्र बनकर उभरेगा, जहां सुरक्षा और स्थिरता के लिए सभी देश उसकी ओर रुख करेंगे और इसके बदले पाकिस्तान को लाभ मिलेगा। लेकिन यदि ट्रंप की योजना में उसे बाहर रखा गया, तो यह बड़ा अवसर उसके हाथ से निकल सकता है।

दूसरी ओर, पाकिस्तान में सेना के प्रभुत्व वाली सरकार शक्तिशाली जरूर है, लेकिन वह काफी अलोकप्रिय भी है। ऐसे में अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने से देश के भीतर ऐसा विरोध भड़क सकता है, जिसे सरकार शायद संभाल न सके।

फिलहाल तो पाकिस्तान अब्राहम समझौते में शामिल होने के सवाल को टालने में सफल रहा है। उसने अपना पुराना रुख दोहराया है कि वह तब तक इज़रायल को मान्यता नहीं देगा और न ही संबंध सामान्य करेगा, जब तक दो-राष्ट्र समाधान पर सहमति नहीं बनता, जिसमें यरुशलम को फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी बनाया जाए।

पाकिस्तान के भीतर मीडिया और पाकिस्तानी सेना समर्थकों ने भी हमेशा की तरह मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इज़रायल को स्वीकार न करने के पुराने रुख का हवाला देते हुए बयानबाजी तेज कर दी है। लेकिन साथ ही यह चिंता भी दिखाई दे रही है कि इज़रायल का मुद्दा उस कूटनीतिक साख को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसे पाकिस्तान ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मेहरबानी से हाल के समय में हासिल किया है।

पंचायत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

15 अप्रैल तक का समय दिया था, लेकिन तब तक चुनाव नहीं कराए गए। इस पर संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की थी। वहीं, बाद में राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग की ओर से अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर समय बढ़ाने की गुहार की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए गत दिनों खंडपीठ ने चुनाव कराने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया। संभावना जताई जा रही है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ के इस फैसले को राज्य सरकार व चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600